अगस्त 2025, वर्ष-1, अंक-2 पृष्ठ-40, मूल्य-50 / -रूपये

RNI NO. CTBIL/25/A1634

CHATURPOST

खबर वार्ता

लाल आतंक पर अंतिम प्रहार

...और विकास की नई सुबह
पेज 16

रायपुर में अब पुलिस कमिश्नर
पेज 27

CHATURPOST
खबर वार्ता

05 लाल आतंक पर अंतिम प्रहार

छत्तीसगढ़ में लाल आतंक (नक्सलवाद) अपनी अंतिम सांसे ले रहा है। 25 वर्ष पहले जब छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बना तब उत्तरी (सरगुजा संभाग) और दक्षिणी (बस्तर संभाग) हिस्सा पूर तरह लाल आतंक की जद में था। झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे सरगुजा संभाग को तो नक्सलवाद से मुक्त करा लिया गया।

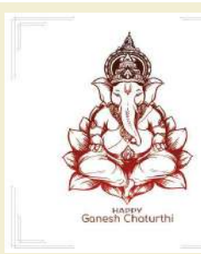

संपादक
शिवानी

प्रबंध संपादक
सुभाष श्रीवास्तव

मार्केटिंग व प्रसार
आशीष वर्मा

विधिक सलाहकार
मो. अजीज हुसैन
मो.93002-05215

ग्राफिक्स लेआउट डिजाइनर
कादिर खान

कार्यालय
रामा भवन बिलासपुर रोड
भनपुरी रायपुर -493221
वाट्सएप- 7587266011

प्रकाश एवं मुद्रक शिवानी द्वारा
रामा भवन बिलासपुर रोड
भनपुरी रायपुर से प्रकाशितव
आसमा पब्लिशर्स इंडिया प्राि.
जयस्तंभ चौक रायपुर से मुद्रित
RNI-CTBIL/25/A1634
www.chaturpost.com

कवर स्टोरी 3

13 उत्तर छत्तीसगढ़ का नक्सल उन्मूलनः भय से विकास...

हालात बदलने की शुरुआत वर्ष 2004 के आसपास हुई। नक्सलियों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए बलरामपुर को पुलिस जिला का दर्जा दिया गया। यहां पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना के साथ ही छत्तीसगढ़ सशस्त्र...

कैबिनेट का विस्तार

21 विष्णुदेव कैबिनेट विस्तार

भाजपा ने संगठन के बाद सत्ता में भी नए चेहरों को महत्व दिया है। कैबिनेट में शामिल 13 में से 10 पहली बार मंत्री बने हैं। राम विचार नेताम, केदार कश्यप और दयालदास बघेल पहले मंत्री रह चुके हैं।

उपराष्ट्रपति चुनाव

24 छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई

उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त बी. सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई हो गया है। सीएम के मीडिया सलाहकार समेत भाजपा नेताओं ने पूर्व सीएम...

नई व्यवस्था

29 एसईसीएल के सीएमडी हरीश दुहन ने दिलाई शपथ

पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में सीएम साय यह ऐलान किया। कमिश्नरी सिस्टम में एडीजी या आईजी रेंक के अफसर की पुलिस कमिश्नर के रुप में पदस्थापना होगी।

08 कवर स्टोरी २
बस्तर में नक्सलवाद
22 राजनीति
युवाओं में आशा की 'किरण'
प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी
26 राजनीति
ज्ञान विज्ञान और अनवरत श्रम
विकसित राष्ट्र की बुनियाद
28 जीएसटी में बदलाव
महंगाई से राहत की आस
30 खेल को बढ़ावा
नवा रायपुर में क्रिकेट एकेडमी
31 कहानी
नई दिशा
35 नए फीचर
अब बिना अकाउंट के भी
वाट्सएप पर कर सकेंगे बातचीत
36 नई सुविधा
साथी एप : खरीदा मोबाइल फोन
नया है पुराना? जान लें
38 सुविधा
अब घर बैठे जांचें चांदी के गहनों
की शुद्धता!

चौंकाने वाले नतीजे में छिपी है रणनीति

सरकार चलाने के लिए सत्ता का अनुभव आवश्यक होता है, अन्यथा स्वार्थी तत्वों के हाथों इस्तेमाल होने में देर नहीं लगती है। अभी विधानसभा सत्र के दौरान वरिष्ठ विधायक जिस तरह सवाल उठाते हैं और जवाब देने वाले नए मंत्री घिर जाते हैं, वह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय होना चाहिए। साय मंत्रिमंडल के ज्यादातर मंत्री पहली बार मंत्री बने हैं और वही विधानसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों से घिर जाते हैं। इस बार नए मंत्रियों के नाम में भी सोशल इंजीनियरिंग दिख रही है। आरंग के विधायक खुशवंत साहेब का अनुसूचित जाति वर्ग में खासा मान है और पार्टी इस वर्ग से गहराई से जुड़ना चाहती थी। इसके पीछे इस वर्ग के असंतुष्ट होने सहित कई राजनीतिक कारण भी हैं।

छत्तीसगढ़ भाजपा में अगस्त में दो बड़े घटनाक्रम हो गए और दोनों ने ही बड़ा संदेश दे दिया है। दोनों के नतीजों की लगातार समीक्षा हो रही है और क्यों, कैसे का जवाब तलाशा जा रहा है। घटनाक्रम के बाद भाजपा के अंदरखाने में एक वर्ग नाराज और असंतुष्ट दिख रहा है, लेकिन भाजपा में नाराजगी को कभी जगह नहीं मिलती। यह एक ऐसी पार्टी है, जो अपने तय लाइन पर चलती है और पार्टी नेताओं को उसी का पालन करना पड़ता है। भाजपा अभी राष्ट्रीय स्तर पर 2047 तक का एक बड़ा विजन लेकर चल रही है। देश की आजादी के सौ साल पूरे होने तक भारत को दुनिया के मंच पर प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य सामने है। यहां तक उस वक्त चंद्रमा पर जाकर वहां से भारत के अगले मिशन की घोषणा करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। ऐसे समय में भाजपा के भीतर भी बदलाव अवश्य दिखेगा। प्रदेश भाजपा ने अपने प्रदेश पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। इनमें कई नामचीन नाम नजर नहीं आए, जो पार्टी के चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। जिन नामों को जगह दी गई, उनमें ज्यादातर चौंकाने वाले हैं। एकाध नाम को छोड़ कर किसी पर विवाद का साया नजर नहीं आया। अब यह नाम क्यों शामिल किया गया है, यह तो पार्टी की रणनीति और सोच पर निर्भर है। पार्टी में महामंत्री का पद पावरफुल होता है। यह पद जिन्हें दिया गया है, वे अभी तक पार्टी की दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता माने जाते रहे हैं। जाहिर है, ऐसा कर पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पहली पंक्ति का उपयोग पार्टी को मार्ग बताने के रूप में किया जाएगा और दूसरी पंक्ति के नेताओं को सामने किया जाएगा, जिससे भविष्य के लिए पार्टी का धरातल मजबूत होता चला जाए। छत्तीसगढ़ भाजपा की टीम में सामाजिक इंजीनियरिंग का विशेष ध्यान रखा गया है और इसका असर प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची तक में दिख रहा है। इससे पहले कम से कम प्रवक्ताओं को जातिगत समीकरण से अलग रख कर केवल योग्य प्रवक्ताओं को आगे बढ़ाने की परंपरा रही है। महिलाओं के अनुपात का भी सूची में ध्यान रखा गया है। प्रदेश की दूसरी राजनीतिक घटना विष्णु देव साय मंत्रिमंडल का विस्तार है। लंबे समय से इसका इंतजार था और भाजपा के ही कुछ वरिष्ठ विधायकों को आस थी कि उन्हें दूसरी सूची में जगह मिल सकती है। विधायकों के सारे दावे किनारे कर दिए गए।

सीएम विष्णु देव साय ने अपने विशेषाधिकार से पहली बार के तीन विधायकों को मंत्री बना दिया। इस फैसले ने भी बता दिया कि पार्टी वरिष्ठों की जगह कनिष्ठ विधायकों को दायित्व देकर आगे बढ़ाना चाहती है, अब यह फैसला कितना सही है, यह आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। सरकार चलाने के लिए सत्ता का अनुभव आवश्यक होता है, अन्यथा स्वार्थी तत्वों के हाथों इस्तेमाल होने में देर नहीं लगती है। अभी विधानसभा सत्र के दौरान वरिष्ठ विधायक जिस तरह सवाल उठाते हैं और जवाब देने वाले नए मंत्री घिर जाते हैं, वह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय होना चाहिए। साय मंत्रिमंडल के ज्यादातर मंत्री पहली बार मंत्री बने हैं और वही विधानसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों से घिर जाते हैं। इस बार नए मंत्रियों के नाम में भी सोशल इंजीनियरिंग दिख रही है। आरंग के विधायक खुशवंत साहेब का अनुसूचित जाति वर्ग में खासा मान है और पार्टी इस वर्ग से गहराई से जुड़ना चाहती थी। इसके पीछे इस वर्ग के असंतुष्ट होने सहित कई राजनीतिक कारण भी हैं। खुशंवत साहेब ने विधानसभा चुनाव के तीन माह पहले ही कांग्रेस छोड़ कर भाजपा की सदस्यता ली थी और टिकट मिलने पर आरंग से जीत भी गए। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए दुर्ग से गजेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र के परिवार का संघ परिवार से पुराना नाता है और इस सेवा का फल भी मिला है। जबकि सामान्य वर्ग और बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने से रिक्त हुए एक स्थान पर अंबिकापुर के राजेश अग्रवाल को जगह दी गई है। इससे अग्रवाल समाज की रिक्तता की पूर्ति हो गई है। इन समीकरणों के बीच बनी प्रदेश पदाधिकारी और साय की टीम के सामने अब आने वाले तीन साल चुनौती रहेंगे। इन्हीं के कामकाज के दम पर भाजपा को अगले विधानसभा चुनाव का सामना करना है।

लाल आतंक पर अंतिम प्रहार

शिवानी

छत्तीसगढ़ में लाल आतंक (नक्सलवाद) अपनी अंतिम सांसे ले रहा है। 25 वर्ष पहले जब छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बना तब उत्तरी (सरगुजा संभाग) और दक्षिणी (बस्तर संभाग) हिस्सा पूर तरह लाल आतंक की जद में था। झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे सरगुजा संभाग को तो नक्सलवाद से मुक्त करा लिया गया। इधर बस्तर से निकलकर नक्सली राजधानी रायपुर के करीब तक पहुंच गए। गरियाबंद, धमतरी और अविभाजित राजनांदगांव में नक्सली उत्पात मचाने लगे। 2008 आते-आते नक्सलवाद चरम पर पहुंच गया था। अब हालात बदल रहे हैं। नक्सली घटनाओं में कमी आई है। इसका असर बस्तर संभाग के विकास पर पड़ा है। सरकारी योजनाएं और सुविधाएं अंदरुनी क्षेत्रों तक पहुंचने लगी है।

मार्च 2026 तक नक्सलवाद के अंत का लक्ष्य

सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य है। बस्तर में अभी नक्सल उन्मूलन अभियान जोर-शोर से संचालित है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी रणनीति के साथ काम चल रहा है।

आक्रामक अभियान के साथ विकास कार्य

नक्सलवाद के खात्मे के लिए आक्रामक अभियान शुरू किया गया। रणनीति के तहत सुरक्षाबल नक्सलियों को पीछे धकेल रहे हैं। नक्सलियों के कब्जे से मुक्त कराए गए क्षेत्र में सुरक्षाबलों के नए कैंप खोले जा रहे हैं। इसके जरिये स्थानीय लोगों तक शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा। बस्तर के लोगों में सरकार भरोसा और विश्वास बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पिछले 20 महीनों में 450 नक्सली मार गिराए गए हैं और 1578 को पकड़ा गया है।

नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025

छत्तीसगढ़ सरकार की नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025 के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि, शस्त्र के बदले मुआवजा, घोषित ईनाम की राशि, प्रशिक्षण, रोजगार और समानजनक जीवन की गारंटी दी जा रही है। नियद नेल्लानार और लोन वर्राटू जैसी योजनाओं के तहत बस्तर के गांवों में सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।

नक्सलवाद के खिलाफ जाग चुका आदिवासी समाज

आज बस्तर का आदिवासी समाज नक्सलवाद के खिलाफ जाग चुका है। ग्रामीण शासन-प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बस्तर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सुरक्षा कैंपों के माध्यम से गांवों में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। स्कूल फिर से खुल रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और युवा हिंसा के बजाय विकास की राह चुन रहे हैं।

हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का सफाया कर देंगे

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी और अथक प्रयासों से ही नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई सफल हो रही है। जिस तरह से सुरक्षा बलों साहस, धैर्य और प्रतिबद्धता के साथ माओवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, उसने दुनिया भर के सुरक्षा बलों को चकित कर दिया है। मुझे पता है कि हमारे जवान जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। यह हमारे सुरक्षा बलों पर भरोसा ही है जिससे प्रेरित होकर मैं बार-बार कहता हूँ कि हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का सफाया कर देंगे।

अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
(23 जून 2025 को रायपुर दिया बयान)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मौजूदा समय में जिस तरह से हमारे सुरक्षाबल काम कर रहे हैं, उसे देखते हुए हम यह लक्ष्य बहुत जल्द प्राप्त कर लेंगे।

-विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

नक्सलवाद की रात ढल रही विकास की नई सुबह का उदय

बस्तर में नक्सलवाद की रात अब ढल रही है और विकास की नई सुबह का उदय हो चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में प्रदेश को नक्सलमुक्त बनाने के संकल्प के साथ दृढ़ता से कार्य कर रही है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल उन्मूलन करना हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

नक्सल उन्मूलन के साथ बस्तर का विकास भी तेजी से किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की संगठित रणनीति एवं जनभागीदारी के चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से बदलाव आ रहा है। पुलिस और केंद्रीय बलों के संयुक्त प्रयासों से कई नक्सल गढ़ों में विकास की किरण पहुंची है, जिससे जनता का विश्वास सरकार की योजनाओं में और मजबूत हुआ है। सरकार का अब पूरा ध्यान बस्तर को नए औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने पर है, जिससे युवाओं को रोजगार और आदिवासी समुदायों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।

-विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

बस्तर में नक्सलवाद

एस कुमार

बस्तर के इतिहास में पहली नक्सली घटना बीजापुर के वंदेपारा में हुई थी। यह 1980 के आसपास की बात है। नक्सलियों ने श्रमिकों को मजदूरी नहीं देने के आरोप में वन विभाग के एक कर्मचारी के साथ मारपीट की थी। इसी तरह नक्सलियों ने एक-एक कर आदिवासियों के साथ हो रहे शोषणा का प्रतिकार किया। धीरे-धीरे नक्सली लोगों के बीच अपनी पैठ के साथ ताकत बढ़ाते चले गए और वसूली करने लगे। समय के साथ जंगल में वैध- अवैध काम बढ़ने लगा, इसके साथ ही नक्सलियों की उगाही भी बढ़ती चली गई।

सरकार ने छीन लिए पुलिस वालों के हथियार

छत्तीसगढ़ की पहली कांग्रेस सरकार के दौरान बस्तर में थानों पर नक्सली हमले बढ़ गए थे। इसे देखते हुए सरकार ने वहां के थानों से पूरे हथियार हटा लिए। पुलिस को शस्त्र वीहिन कर दिया। सरकार का तर्क था कि नक्सली हथियार लूटने के लिए थानों पर हमला करते हैं, थानों में हथियार नहीं रहेंगा तो नक्सली हमला भी नहीं करेंगे। सरकार के इस फैसले से नक्सलियों को खुला मैदान मिल गया। इससे नक्सली घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी।

छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में नक्सलवाद

छत्तीसगढ़ के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सली सक्रिय रहे हैं। राज्य की सीमाएं सात राज्यों से लगी हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। झारखंड से लगा सरगुजा संभाग काफी पहले नक्सलवाद से मुक्त कराया जा चुका है। इसी तरह मध्य प्रदेश से लगे कवर्धा जिला में भी लंबे समय से नक्सली घटना नहीं हुई है। महाराष्ट्र से लगे अविभाजित राजनांदगांव जिला में भी नक्सलवाद लगभग खात्मे की ओर है। ओडिशा से लगे गरियाबंद, धमतरी और रायगढ़ में अब नक्सली सिमट चुके हैं। तेलंगाना और आंधप्रदेश से बस्तर संभाग लगा हुआ है। नक्सल हिंसा के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित यही क्षेत्र रहा है।

सलवा जुडूम का दौर

2005 में नक्सली हिंसा के खिलाफ बस्तर के लोग उठ खड़े हुए। बस्तर टाइगर के नाम प्रसिद्ध कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। इसे सलवा जुडूम नाम दिया गया। इस आंदोलन के कारण ग्रामीणों में जागरुकता बढ़ी और वे नक्सलियों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। इससे नक्सलियों को खतरा महसूस होने लगा। अपनी धमक बनाए रखने के लिए नक्सलियों ने ग्रामीणों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 30 हजार से ज्यादा ग्रामीणों को राहत कैंपों में शरण लेना पड़ा। ग्रामीणों में नक्सलियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। बड़ी सेंया में युवा नक्सलियों के खिलाफ हथियार उठाने लगे। एसपीओ और कोया कमांडों के रुपए में उनकी भर्ती हुई। इस बीच 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सलावा जुडूम आंदोलन और एसपीओ पर रोक लगा दिया।

मनवाता को शर्मसार करने वाली एर्राबोर की घटना

सलवा जुडूम के दौरान 25 अप्रैल 2006 को सुकमा जिले के थाना एर्राबोर से लगभग 12 किलोमीटर दूर मनीकोंटा में एक घटना हुई। मनीकोंटा के ग्रामीण जो उस समय दोरनापाल के सलवा जुडूम कैंप में रह रहे थे। अपना घरेलू समान लेने के लिए 58 ग्रमीणजन पैदल अपने गांव जा रहे थे तब 100-125 नक्सलियों ने उन्हें अगवा कर लिया और उन्हें जंगल में ले जाकर धारदार हथियारों से 15 ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर उनके शवों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर फेंक दिया था।

जनअदालतों में हत्याएं

नक्सली संगठन जब मन में आया गांवों में जन अदालत लगाते और उल्टे-सीधे आरोप लगाकर ग्रामीणों की बेदम पिटाई की, घर फूंक दिया, दो-चार का गला रेत दिया। नक्सलियों ने सलवा जुडूम के दौरान कई अन्य गांवों में भी हमले किए। इसका सबसे बड़ा खामियाजा निर्दोष आदिवासियों को भुगतना पड़ा। अभी हाल ही में दंतेवाड़ा में एक सरपंच प्रत्याशी की हत्या कर दी गई, क्योंकि वे पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रहे थे। नक्सलियों ने न केवल हत्याएं कीं, बल्कि ग्रामीणों को डराने के लिए लैंडमाइंस और आईईडी का इस्तेमाल किया। इन हमलों में कई बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी अपनी जान गंवा चुके हैं।

स्कूल और अस्पातालों को बनाया निशाना

नक्सलवाद ने बस्तर को आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा बना दिया। नक्सलियों ने शिक्षा को निशाना बनाया। स्कूलों को ढहाया और शिक्षकों को धमकाया गया। इससे आदिवासी बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ा। अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाया, जिससे ग्रामीणों को बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिलीं। सड़कों, पुलों और मोबाइल टॉवर, बिजली लाइनों को नष्ट किया, जिससे बस्तर विकास की मेयधारा से कट गया। नक्सलियों ने युवाओं को भ्रमित कर उन्हें हथियार उठाने के लिए मजबूर किया, जिससे कई परिवार अपने बच्चों को खो बैठे।

2004 से शुरु हुई नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई

बस्तर में नक्सलवाद से मुक्त कराने का प्रयास 2004 में शुरु हुआ। तब प्रदेश में पहली बार डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे ओपी राठौर को सरकार ने राज्य पुलिस की कमान सौंपी। इसके साथ नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनने लगी। नक्सलियों की गोरिल्ला लड़ाई का मुकाबला करने के लिए पुलिस वालों को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाने लगी। इसके लिए कांकेर में जंगल वारफेयर कॉलेज की स्थापना हुई। जंगल की लड़ाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई।

2009 के बाद एक साथ कई मोर्चों पर जंग

दिल का दौरा पड़ने की वजह से डीजीपी ओपी राठौर का निधन हो गया। इसके बाद सरकार ने केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी में काम कर रहे छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस विश्वरंजन को डीजीपी बनाया गया। विश्वरंजन के कार्यालय में नक्सलियों और नक्सलवाद के खिलाफ एक साथ कई मोर्चों पर जंग शुरू हुई। केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि नक्सलवाद केवल राज्य की कानून- व्यवस्था का विषय नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू हुई। जंगल में फोर्स ने सर्चिंग और नक्सल उन्मूलन अभियान शुरू किया तो इधर, शहरी क्षेत्रों में बैठे उनके लोग भी बेनकाब होने लगे। लाल आतंक के इस शहरी नेटवर्क के साथ लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, इसके लिए विश्वरंजन को व्यक्तिगत देश के बाहर भी विरोध, आलोचनाओं और हमलों का सामना करना पड़ा।

एसआईबी और एएनओ हुआ सक्रिय

जंगल वारफेयर कॉलेज के जरिये जवान गोरिल्ला वार में तो ट्रेंड होने लगे, लेकिन पुलिस के पास खुफिया सूचनाओं का आभाव था। जंगल में बैठे नक्सलियों को फोर्स की हर हरकत से लेकर सरकार के कदम की जानकारी तो मिल जाती थी, लेकिन फोर्स को उनकी जानकारी नहीं मिल पाती थी। नक्सलियों की खुफिया सूचना जुटाने के लिए स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो (एसआईबी) की स्थापना की गई। आईपीएस गिरधारी लाल नायक के बाद डीआईजी पवन देव को एसआईबी की कमान सौंपी गई। इसके बाद पीएचक्यू में एंटी नक्सल ऑपरेशन (एएनओ) भी सक्रिय हो गया। सुरक्षा के लिए जवानों को एंटी लैंड माइन और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ नाइट विजन के साथ नए-नए हथियार और संसाधन से लैस किया गया।

अब खुफिया सूचनाओं पर ही ऑपरेशन

बस्तर में पुलिस का खुफिया नेटवर्क काफी मजबूत हो चुका है। अब बस्तर में पुलिस पुता खुफिया सूचनाओं के आधार पर ही नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। खुफिया इनपुट के आधार पर ही सुरक्षाबलों ने नक्सली संगठन के महासचिव वसवराजू समेत कई बड़े नक्सली लीडरों को पिछले आठ महीने में ढेर किया है।

टूटने लगा शहरी सप्लाई लाईन

एसआईबी ने थोड़े ही समय में न केवल जंगल बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी सक्रिय नक्सली और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाने लगी। नक्सलियों के लिए शहरी क्षेत्रों में काम करने वालों पर लगाम कस गया। शहरी क्षेत्रों से कई लोग पकड़े गए। इसका असर जंगल में बैठे नक्सलियों की सप्लाई पर पड़ा। इसका असर बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों पर भी दिखा।

पुलिस पर आरोपों और मुकदमों की झड़ी

बस्तर में पुलिस ने जैसे ही नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक रुख ओंतियार किया, पुलिस और सरकार के सामने नई संकट खड़ी हो गई। पुलिस पर मानव अधिकारों के हनन के आरोपों की झड़ी लग गई। लगभग हर मुठभेड़ पर सवाल उठाए जाने लगे। तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ पुलिस की कार्यवाही रोकने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाने लगे। इससे सरकार और पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा।

पुलिस और फोर्स को बड़ा नुकसान

नक्सलवाद के खिलाफ इस जंग में बस्तर के लोगों के साथ पुलिस और सुरक्षाबल के जवानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। 6 अप्रैल 2010 ताड़मेटला में 75 जवान शहीद हो गए थे, जो देश के नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। बीते 20 सालों में बस्तर में नक्सली हमले में शहीद होने जवानों की एक हजार से अधिक है।

झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हमला

25 मई 2013 को नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनेके पुत्र, महेंद्र कर्मा समेत कई नेताओं की जान चली गई। इसी हमले में घायल हुए वीसी शुक्ला का इलाज के दौरान निधन हो गया। यह घटना नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है।

सुरक्षा बलों के टारगेट पर बड़े नक्सली लीडर

पुलिस अफसरों के अनुसार मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे की डेड लाइन तय करने के साथ ही सरकार ने फोर्स के लिए टारगेट भी तय कर दिया था। फोर्स को नक्सलियों के 31 टॉप लीडर की सूची सौंपी गई है। इनमें पोलित ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी के साथ रीजन और राज्यों की कमेटी के नक्सली लीडर शामिल हैं। इनमें से कुछ लीडरों को हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर भी कर दिया है। इनमें नक्सली संगठन का सेंट्रल कमेटी का सदस्य और महासचिव बसव राजू भी शामिल है।

पूरे देश में सिमट रहा नक्सलवाद

इसी साल मई में जारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में देश में नक्सलवाद के सिमटने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, 2025 में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों के तहत सुरक्षा बलों ने पिछले 4 महीनों में 197 कट्टर नक्सलियों को ढेर किया है। 2014 में 35 जिले नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित थे और 2025 तक घटकर सिर्फ 6 रह गए है। इसी तरह नक्सल प्रभावित जिले 126 से घटकर सिर्फ 18 रह गए हैं। 2014 में 76 जिलों के 330 थानों में 1080 नक्सली घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि 2024 में 42 जिलों के 151 थानों में सिर्फ 374 घटनाएं दर्ज की जाएंगी।

2014 में नक्सली हिंसा में 88 सुरक्षाकर्मी बलिदानी हुए थे, जो 2024 में घटकर 19 रह गए। मुठभेड़ों में मारे गए नक्सलियों के आंकड़े 63 से बढ़कर 2089 हो गई है।

2024 में 928 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 2025 के पहले चार महीनों में अब तक 718 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

2019 से 2025 तक केंद्रीय बलों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर नक्सल प्रभावित राज्यों में कुल 320 कैंप स्थापित किए हैं, जिनमें 68 नाइट-लैंडिंग हेलीपैड शामिल हैं।

33 में से 14 जिले नक्सल प्रभावित

बस्तर को नक्सल मुक्त जिला घोषित किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के 33 में से 14 जिला अब भी प्रभावित हैं। इनमें बीजापुर, दंतेवाडा, सुकमा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और नारायणपुर के साथ राजनांदगांव, मोहला मानपुर अंबागढ़, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, कबीरधाम और मुंगेली शामिल हैं।

2025 में नक्सलियों को लगे बड़े झटके

20 जून 2025- कांकेर जिले के छोटेबेठिया इलाके में हुई मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए।

18 जून 2025- छत्तीसगढ़-आंध्र सीमा पर मुठभेड़ में केंद्रीय कमेटी मेंबर समेत 3 नक्सली ढेर।

07 जून 2025- सुकमा में पांच नक्सली मारे गए, इनमें दो महिलाएं भी शामिल थीं।

06 जून 2025- तेलंगाना स्टेट कमेटी का सदस्य भास्कर मारा गया।

05 जून 2025- सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम मारा गया।

21 मई 2025- शीर्ष नक्सली नेता बसवराजू और 28 नक्सली ढेर कर दिए गए।

15 मई 2025- बीजापुर के करेंगुट्टा पहा पर 16 दिन तक चले ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए।

12 अप्रैल 2025- दंतेवाा-बीजापुर बार्डर पर मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर।

31 मार्च 2025- दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर 45 लाख की इनामी महिला नक्सली मारी गई।

29 मार्च 2025- सुकमा में नक्सली मुठभे में सुरक्षाबलों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया।

20 मार्च 2025- बीजापुर और कांकेर में हुए दो नक्सल एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए।

9 फरवरी 2025- बीजापुर जिले में मुठभे, 31 लाल आतंकी मारे गए।

20-21 जनवरी 2025- गरियाबंद जिले में मुठभेड़, 16 नक्सली ढेर कर दिए गए।

19 जनवरी 2025- केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ चलपथी व 14 नक्सली मारे गए।

16 जनवरी 2025- बीजापुर जिले में मुठभे में 18 नक्सली मार गिराए गए।

20-21 जनवरी 2025- गरियाबंद जिले में मुठभेड़, 16 नक्सली ढेर कर दिए गए।

19 जनवरी 2025- केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ चलपथी व 14 नक्सली मारे गए।

16 जनवरी 2025- बीजापुर जिले में मुठभे में 18 नक्सली मार गिराए गए।

उत्तर छत्तीसगढ़ का नक्सल उन्मूलन
भय से विकास की ओर सफर

विशेष संवाददाता

उत्तर छत्तीसगढ़ का भूगोल और सामाजिक संरचना उसे कई मायनों में संवेदनशील बनाता है। झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटा यह इलाका, कभी नक्सलवाद के गहरे साए में जकड़ा हुआ था। झारखंड के नक्सलियों ने यहां के स्थानीय युवाओं को अपने साथ मिलाकर न केवल नेटवर्क मजबूत किया, बल्कि सीमावर्ती ग्रामों से होते हुए सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी।

वर्ष 2000 के आसपास का दौर आज भी यहां के लोग भूल नहीं पाए हैं। शाम ढलते ही गांवों के दरवाजे बंद हो जाते थे, यह मूक दृश्य नक्सली भय की कहानी कहता था। रात में कोई वाहन निकलता तो भीतर की लाइट जलाने की हिमत नहीं होती थी। दुकानों और घरों के बाहर एक बल्ब जलाना भी खतरे से खाली नहीं था। अदृश्य आतंक का यह वातावरण विकास को रोक रहा था और लोगों के मन में एक निरंतर भय पल रहा था।

वर्ष 2004: आशा की किरण

हालात बदलने की शुरुआत वर्ष 2004 के आसपास हुई। नक्सलियों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए बलरामपुर को पुलिस जिला का दर्जा दिया गया। यहां पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना के साथ ही छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती हुई। पुलिस जिला बनने के बाद नक्सलियों के विरुद्ध एक संगठित अभियान की रूपरेखा तैयार हुई। झारखंड पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया गया, जिससे सीमापार की सूचनाएं तत्काल साझा हो सकें। बलरामपुर और जशपुर जिले की पुलिस ने विशेष रूप से सूचना तंत्र को मजबूत किया। यह रणनीति आगे चलकर निर्णायक साबित हुई।

आइपीएस एसआरपी कल्लूरी की भूमिका अहम

जब बलरामपुर में एसपी के रूप में एसआरपी कल्लूरी की पदस्थापना हुई तो उन्होंने अभियान को नए तरीके से शुरू किया। उनका पहला लक्ष्य था ग्रामीणों का विश्वास जीतना। कल्लूरी ने गांवों में जाकर सीधे संवाद किया, पुलिस और सशस्त्र बल की उपस्थिति को सामान्य और भरोसेमंद बनाया। बिना ज्यादा शोर-शराबे के, हर गांव में पुलिस ने विश्वसनीय मुखबीर नियुक्त किए। इनके जरिए नक्सलियों की गतिविधियों की सूचनाएं लगातार पुलिस तक पहुंचने लगीं। धीरे-धीरे पुलिस ने सफलता पाना शुरू किया। मुठभेड़ों में नक्सलियों को मार गिराया गया और कई को जिंदा पकड़ने में भी सफलता मिली। लेकिन यह आसान नहीं था। नक्सली भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस दौर में रामचंद्रपुर थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों की शहादत हुई। नक्सलियों ने प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों की हत्या कर माहौल में और दहशत फैलाने की कोशिश की। साधन-संपन्न ग्रामीण अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए।

मनोवैज्ञानिक मोर्चा ने किया काम

ऐसे कठिन समय में एसपी कल्लूरी ने समझा कि केवल हथियार से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती,ग्रामीणों के दिल और दिमाग जीतना होगा। उन्होंने गांवों में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों की बैठकें आयोजित कराईं, जिसमें नक्सल हिंसा से हो रहे नुकसान को सीधे ग्रामीणों के सामने रखा गया। नक्सलियों की छद्म नीति को उजागर करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सहारा लिया गया। नुक्कड़ नाटक और गीतों के माध्यम से यह संदेश फैलाया गया कि नक्सलवाद विकास का दुश्मन है। इसका असर दिखा और ग्रामीणों में पुलिस और प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ने लगा।

मनोवैज्ञानिक मोर्चा ने किया काम

ऐसे कठिन समय में एसपी कल्लूरी ने समझा कि केवल हथियार से यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती,ग्रामीणों के दिल और दिमाग जीतना होगा। उन्होंने गांवों में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों की बैठकें आयोजित कराईं, जिसमें नक्सल हिंसा से हो रहे नुकसान को सीधे ग्रामीणों के सामने रखा गया। नक्सलियों की छद्म नीति को उजागर करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सहारा लिया गया। नुक्कड़ नाटक और गीतों के माध्यम से यह संदेश फैलाया गया कि नक्सलवाद विकास का दुश्मन है। इसका असर दिखा और ग्रामीणों में पुलिस और प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ने लगा।

यह था नक्सल उन्मूलन का आखिरी मोर्चा

यह इलाका झारखंड के बूढ़ा पहाड़ से सटा होने के कारण, उधर के नक्सली कभी-कभी यहां आते थे। लेकिन स्थिति तब बदली, जब सामरी से चुनचुना और पुंदाग तक पक्की सड़क का निर्माण हो गया। सड़क ने न केवल पुलिस और प्रशासन की पहुंच आसान बनाई, बल्कि विकास के साधन भी इन गांवों तक पहुंच गए।अब यहां नक्सल गतिविधियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। ग्रामीण निश्चिंत होकर रात में भी घरों के बाहर रोशनी जला सकते हैं। जहां कभी आतंक की छाया थी, वहां अब स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और बाजार फल-फूल रहे हैं।

विकास की ओर बढ़ा कदम

नक्सल उन्मूलन के बाद यह क्षेत्र अब तेजी से विकास की राह पर है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं यहां पहुंच रही हैं। खेती-किसानी में आधुनिक तकनीक अपनाई जा रही है। ग्रामीण रोजगार योजनाओं के जरिए युवाओं को काम मिल रहा है।यह बदलाव सिर्फ पुलिस की गोलियों से नहीं आया है।यह आया है पुलिस, प्रशासन और जनता के संयुक्त प्रयास से, जिसमें विश्वास, संवाद और विकास ने निर्णायक भूमिका निभाई।

निर्णायक कार्यवाहीं

विश्वास की इस नींव पर पुलिस ने लगातार आक्रामक अभियान जारी रखा। मुठभेड़ों में कई बड़े नक्सली मारे गए, कुछ को जिंदा पकड़ा गया। उनके मारे जाने या जेल जाने से नेटवर्क कमजोर पड़ता गया। स्थानीय युवा, जो पहले नक्सली संगठन में शामिल हुए थे, धीरे-धीरे घर लौटने लगे।ऐसे युवाओं के खिलाफ भी पुलिस ने सेत कार्रवाई की, ताकि यह संदेश जाए कि कानून के खिलाफ जाने वालों के लिए जगह नहीं है। इस दौरान सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिलों में सक्रिय नक्सलियों का दायरा सिमटते-सिमटते बलरामपुर के समरी थाना क्षेत्र तक रह गया। यहां भी केवल दो दुर्गम गांव–चुनचुना और पुंदाग में उनकी गतिविधियां बची थीं।

सुपर कॉप्स

बस्तर को नक्सलवाद से मुक्ति और विकास की राह पर लाने में वहां तैनात पुलिस, राज्य सशस्त्र बल के साथ केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों का सबसे बड़ा योगदान है। बस्तर की शांति के लिए हजारों जवान बलिदान हुए हैं। राज्य पुलिस के कई जवान और अफसर ऐसे हैं जिनकी पूरी या सर्विस का अधिकांश समय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ही गुजरा है। यही सुपर कॉप्स बस्तर के असली हीरो हैं। इनमें से हर एक के नाम का उल्लेख कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन अभी नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ दो आईपीएस का उल्लेख जरुर करेंगे। इनमें एक हैं डीआईजी कमल लोचन कश्यप और दूसरे आईजी बस्तर सुंदरराज पी हैं।

सुंदरराज पी

बस्तर में नक्सल मोर्चे की कमान रेंज आईजी सुंदरराज पी ने संभाल रखी है। 2003 बैच के आईपीएस सुंदरराज को 4 नवंबर 2019 को प्रभारी आईजी के रुप में बस्तर में पदस्थ किया गया था। बस्तर रेंज आईजी के पद पर काम करने वाले संभवतः वे पहले अफसर हैं। आईपीएस सुंदरराज कई सालों से नक्सल प्रभावित जिलों में ही तैनात रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहला एनकाउंटर भी सुंदरराज ने किया था। तब वे कोरबा के एसपी थे।

कमल लोचन कश्यप

कमल लोचन कश्यप अभी डीआईजी दंतेवाड़ा हैं। 1994 में वे बतौर डीएसपी राज्य पुलिस सेवा में शामिल हुए। 2008 में उन्हें आईपीएस अवार्ड हुआ। वीरता और सराहनीय सेवा के लिए उन्हें अब तक कई बार पुरस्कृत किया जा चुका है। मूल रुप से बस्तर के रहने वाले कश्यप अपनी पूरी सेवा के दौरान बहुत कम समय मैदानी इलाकों में रहें हैं। उनका ज्यादातर समय नक्सली क्षेत्रों में ही गुजरा है। गरियाबंद और राजनांदगांव से लेकर बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों में दर्जनों मुठभेड़ को वे खुद लीड कर चुके हैं।

ज्यादातर नक्सल इलाकों में रहे तैनात

आईपीएस सुंदरराज सरगुजा, कबीरधाम, राजनांदगांव, कोरबा आदि नक्सल प्रभावित इलाकों के एसपी भी रहे हैं। वह वर्ष 2010 में बस्तर एसपी रहे। इसके अलावा नारायणपुर, कोंडागांव आदि जिलों में भी रहे। नक्सली इलाकों की अच्छी समझ होने के कारण जगदलपुर के एसपी रहने के दौरान उन्हें डीआईजी दंतेवाड़ा और प्रभारी आईजी बस्तर भी बनाया गया। वीरता और सराहनीय सेवा के लिए उन्हें अब तक कई बार पुरस्कृत किया जा चुका है।

उम्मीद और विकास की नई सुबह

नसीम अहमद खान, उप संचालक

बस्तर अब विकास, विश्वास और बदलाव की नई इबारत लिख रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के मजबूत राजनीतिक संकल्प और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से यहाँ शांति बहाल हो रही है और विकास तेजी से अपना पांव पसार रहा है। सीएम विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने ऐसा निर्णायक अभियान चलाया है कि नक्सलवाद अपनी अंतिम साँसें गिन रहा है। इस अवधि में 435 नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए, 1,432 ने आत्मसमर्पण किया और 1,457 पकड़े गए।

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने देश की सबसे बेहतर पुनर्वास नीति लागू की है। इसमें तीन वर्ष तक प्रतिमाह दस हजार रुपये स्टाइपेंड, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार से जोड़ने की व्यवस्था तथा नकद इनाम व कृषि अथवा शहरी भूमि प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कर बस्तर को शांति और प्रगति की भूमि बनाया जाए। सीएम साय का कहना है कि बस्तर में बंदूक की जगह अब किताब, सड़क और विकास की गूंज सुनाई दे रही है। हमारा लक्ष्य बस्तर को विकास के मार्ग में अग्रणी बनाना है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास को भी अभूतपूर्व गति प्रदान की गई है। आबादी के बाद पहली बार अबूझमाड़ के रेकावाया गाँव में स्कूल बन रहा है, जहाँ कभी माओवादी अपने स्कूल चलाते थे। हिंसा के कारण बंद पड़ें लगभग 50 स्कूल पुनः खोले गए हैं, नए भवन तैयार हुए हैं और सुरक्षा कैंप खुलने के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ तेजी से पहुँच रही हैं। बिजली के मामले में भी बस्तर ने एक नया इतिहास रचा है, हिडमा के पैतृक गाँव पूर्वार्ति समेत कई दुर्गम गाँवों में पहली बार विद्युत व्यवस्था पहुँची है। बीजापुर के चिलकापल्ली में 77 वर्षों बाद 26 जनवरी 2025 को पहली बार बिजली का बल्ब जला।

सड़कों के रास्ते पहुंच रहा विकास

बस्तर में सड़क निर्माण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 275 किलोमीटर लंबी 49 सड़कें और 11 पुल तैयार हो चुके हैं। केशकाल घाटी चौड़ीकरण व 4-लेन बाईपास निर्माण के साथ-साथ इंद्रावती नदी पर नया पुल बनने से कनेक्टिविटी आसान हुई है।

रेल नेटवर्क का विकास

रावघाट से जगदलपुर 140 किलोमीटर नई रेल लाईन परियोजना की स्वीकृति मिली है। इस परियाजना से बस्तर के विकास को चौमुखी प्रगति मिलेगी। बस्तर में के.के लाईन के दोहरीकरण का काम तेजी से कराया जा रहा है। तेलंगाना के कोठागुडेम से दंतेवाड़ा किरंदूल को जोड़ने वाली 160 किलोमीटर रेल लाईन का सर्वे अंतिम चरण में है इसका 138 किलोमीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ में होगा, साथ ही 607 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं जिनमें से 349 को 4जी में बदला गया है।

नियद नेल्ला नार योजना

गाँवों तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए नियद नेल्ला नार अर्थात आपका अच्छा गाँव योजना लागू की गई है जिसके तहत 54 सुरक्षा कैंपों के 10 किलोमीटर के दायरे में 327 से अधिक गाँवों में सड़क, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम आवास, मोबाइल टावर व वन अधिकार पट्टे जैसी सुविधाएँ दी जा रही हैं। नियद नेल्ला नार योजना के चलते 81 हजार से अधिक ग्रामीणों के आधार कार्ड, 42 हजार से अधिक ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड, 5 हजार से अधिक परिवारों को किसान सम्मान निधि, 2 हजार से अधिक परिवारों को उज्जवला योजना, 98 हजार से अधिक हितग्राहियों को राशन कार्ड प्रदाय किये गए है। इस योजना ने विश्वास का ऐसा वातावरण बनाया है कि कई गाँवों में पहली बार पंचायत चुनाव, ध्वजारोहण, सरकारी योजनाओं की पहुंच संभव हो पाई है।

नए प्रोजेक्ट्स

बस्तर की जीवन दायिनी इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित महत्वाकांक्षी बोधघाट परियोजना को लेकर मुेयमंत्री विष्णु देव साय ने प्रभावी पहल शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्होंने बोधघाट सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने का आग्रह भी किया है। 50 हजार करोड़ रूपये की लागत वाली इस परियोजना के माध्यम से बस्तर अंचल में लगभग 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा और 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी होगा। सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु इंद्रावती नदी और महानदी को जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

आर्थिक स्वावलंबन

आर्थिक मोर्चे पर भी बस्तर में नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। तेंदूपत्ता मानक बोरे की दर 4000 से बढ़ाकर 5500 रूपये कर दी गई है, जिससे 13 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। तेंदूपत्ता संग्रहकों के लिए विष्णु देव साय की सरकार ने चरण पादुका योजना फिर से आरंभ की है, और 13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को इसका लाभ मिला रहा है। मुेयमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 90,273 युवाओं को प्रशिक्षित कर 39,137 को रोजगार मिला है। नई उद्योग नीति 2024-30 में बस्तर के लिए विशेष पैकेज है, जिसके तहत यहाँ स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को 45 प्रतिशत पूँजी अनुदान और आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार देने पर पाँच वर्षों तक 40 प्रतिशत वेतन सब्सिडी दी जा रही है। नागरनार स्टील प्लांट के सहायक उद्योगों को ध्यान में रखते हुए नियानार में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।

बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम

सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी बस्तर नई पहचान बना रहा है। जहाँ कभी गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, वहाँ अब बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों की धूम है। बस्तर ओलंपिक में 1.65 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, वहीं बस्तर पंडुम में 47 हजार कलाकारों ने जनजातीय संस्कृति को वैश्विक मंच दिया। बैगा, गुनिया और सिरहा जैसे पारंपरिक जनजातीय जनों को 5000 रुपये वार्षिक सेमान निधि दी जा रही है।

www.chaturpost.com

नक्सलवाद - एक : दोनों कुओं का पानी

सुबह की पहली किरण से पहले ही खाकी वर्दियों ने गाँव को घेर लिया। कौन है वह? दरवाजे खटखटाए गए। रामलाल गोंड की साँसें तेज हो गईं। उसकी छोटी सी झोपड़ी के कोने में बंधी बकरी ने आहत स्वर में मिमियाई।

सरकार को ख़बर मिली है... तुहारे गाँव से ही कोई नक्सलियों को राशन पहुँचा रहा है! हवलदार की आवाज कर्णफोडू थी।

रामलाल ने हाथ जोड़े–हुजूर, हम ग़रीब... चुप! एक ठोकर ने उसे गिरा दिया। अनाज का बोरा, दो मुर्गियाँ–सब जब्त। पीछे से उसके बेटे की सिसकनी सुनाई दी।

ढलती शाम को जंगल से आए वे लोग। उनकी आँखों में गुस्सा था। पुलिस को खबर किसने दी? रामलाल का गला सूख गया। उसने मना किया, पर किसने सुनी? उसकी लाठी और एकमात्र बकरी उनके साथ चली गई।

अगली भोर को पुलिस ने उसके खेत में गड्ढा खोदकर एक पुराना पिस्तौल दबा दिया। नक्सली साबित हुआ! रामलाल की पीठ पर गोली का निशान बन गया। जंगल में उसके शव के पास वे लोग खड़े थे। एक ने कहा–यह भी पुलिस का मुखबिर था।

आकाश में एक चील चुपचाप चक्कर लगा रही थी। नीचे, दोनों कुओं का पानी एक ही था–खारा।

नक्सलवाद - दो : खाकी और लाल

सुबह की धुंध में जब पहली गोली की आवाज गूँजी, महादेव गोंड ने अपनी झोपड़ी की दीवार से चिपककर साँस रोक ली। बाहर खाकी वर्दियों की जीप ने गाँव को घेर लिया था।
हवलदार ठोकर मारते हुए अंदर घुसा, सुना है तेरा बेटा नक्सलियों को चावल देता है? सरकार के खिलाफ गद्दारी?
महादेव के हाथ जुड़ गए, हुजूर, उसने तो मना किया था...पर उन्होंने बंदूक दिखाकर–
चुप! एक थप्पड़ ने उसके मुँह से खून की लकीर बहा दी।
शाम को जब नक्सली आए, तो उनकी आँखों में वही सवाल था, सुना है तूने पुलिस को हमारे बारे में बताया?
रात के अँधेरे में महादेव ने अपनी एकमात्र बकरी को उनके हवाले कर दिया–ये लो... बस मेरे बेटे को–
सुबह उसकी लाश मिली।
पुलिस रिपोर्ट - नक्सलियों ने मारा।
जंगल में चिपकाया गया पोस्टर यह पुलिस का मुखबिर था।
उसके बेटे ने दोनों रिपोर्टों को जलाकर अपने पिता की चिता सजाई।

नक्सलवाद - तीन : विकास का भूत

कंपनी के बोर्डरूम में एमडी ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए : बस्तर की खदान से 500 करोड़ का मुनाफा। पर्यावरण क्लीयरेंस? हो गया – कुछ आदिवासी पेड़ों को देवता मानते हैं, ये सुपरस्टीशन है।
उसी रात उसे सपने में एक युवक दिखा–उसकी आँखों में जंगल के उजड़ने का दर्द था। एमडी ने गार्ड को बुलाया, पर वह आकृति अदृश्य थी।
अगले दिन अखबार की सुर्खियाँ: नक्सलियों ने माइनिंग ट्रक उड़ाया, 3 सुरक्षाकर्मी मरे।
एमडी ने इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया।
जंगल के किनारे पुलिस ने एक शव खोजा–उसकी जेब में एक फटा हुआ ड्राइंग था: मेरा स्कूल।
एफआईआर. 'आतंकवादी।'
उस रात एमडी ने फिर वही आकृति देखी–अब उसके हाथ में ड्राइंग थी।

नक्सलवाद - चार : जनताना सरकार का हिसाब-किताब

कोर कमेटी की बैठक में कॉमरेड अरुण ने एक्सेल शीट खोली- इस महीने का टारगेट 5 पुलिसवाले, 2 ट्रक, 1 माइनिंग ऑफिस जलाना। परफॉरमेंस: 120 प्रतिशत!
तालियाँ गूँजीं। फिर उसने स्क्रॉल किया, लेकिन जनता का वालंटियर डोनेशन सिर्फ 40 प्रतिशत मिला।
सभा में सन्नाटा। कॉमरेड विशाल खड़ा हुआ, यह गद्दारी है! गाँव वाले सरकारी योजनाओं के लालच में फँस रहे हैं!
अगले दिन गाँव में 'जन अदालत' लगी। तीन 'दोषियों' को पेड़ से बाँधा गया–एक ने पुलिस को रास्ता दिखाया था, दूसरा एनजीओ के साथ काम करता था, तीसरा बस इतना बोला था, हमें अस्पताल चाहिए।
फैसला सुनाया गया, इनकी संपत्ति जनताना सरकार के नाम।
संपत्ति? एक टूटी हुई साइकिल, तीन मुर्गियाँ और एक अधूरी कच्ची दीवाल।

नक्सलवाद - पाँच : एंबुलेंस चालक का डायरी पन्ना

तारीख: 22 मार्च 2013
स्थान : सुकमा-दंतेवाड़ा रोड
लोड : 3 शव
1. सीआरपीएफ जवान (गोली लगने से)
2. नक्सली कमांडर (एनकाउंटर में)
3. गर्भवती आदिवासी महिला (पानी भरने गई थी)
घटना
चेकपोस्ट पर पुलिस ने रोका: फ़ोटो लेनी है–मीडिया को प्रूफ चाहिए।
मैंने पूछा- किसकी?
उन्होंने कहा- जिसकी हेडकाउंट बढ़ाए।
5 किमी आगे नक्सलियों ने बाधा डाली- कॉमरेड की शहादत का वीडियो बनाओ!
महिला का शव पूरी यात्रा में बिना नाम के बैग जैसा पड़ा रहा।
नोट: आज मैंने रिजाइन दे दिया।

नक्सलवाद - छह : खाकी और लाल

प्राइम टाइम का शिकार
अंकिता (एंकर)- स्वागत है एसपी साहब ! नक्सल हिंसा में 80 प्रतिशत कमी... यह कैसे संभव हुआ?
एसपी- जी, हमने 90 जिलों को 70 घोषित कर दिया। नए फॉर्मूले से!
अंकिता: और आदिवासियों का विकास?
एपी: उन्हें 4जी टावर दिए! अब वे नक्सली प्रोपैगंडा यूट्यूब पर देख सकते हैं।
कट टू: स्टूडियो के बाहर एक पत्रकार की डायरी, आज मुझे सस्पेंड कर दिया । कारण- मैंने रिपोर्ट की थी कि जिन 10 जिलों में 66 प्रतिशत हिंसा होती है, वहाँ पुलिस को हॉव टू सर्वाइव ही सिखाया जाता है।

नक्सलवाद - सात : रक्तधारा

नदी की धारा में तीन रंग घुल रहे थे –
सिपाही के यूनिफॉर्म का खाकी,
कॉमरेड के गमछे का लाल,
आदिवासी बच्चे के पेट में फँसी गोली का काला।
एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने नोट किया: यह जल प्रदूषण है।
सरकार ने प्रेस रिलीज जारी की: ये मात्र हल्दी का रंग है।
नक्सलियों ने पर्चा बाँटा: यह क्रांति की लाली है!
बच्चे की माँ ने पंडित से पूछा: कफन किस रंग का लूँ? ये तीनों रंग तो उसके शरीर में ही हैं।

नक्सलवाद - आठ : अंतिम पत्र

प्रिय माँ,
आज मेरी बारी थी 'जन अदालत' में फैसला सुनाने की। तीन आरोपी –
1. एक ने पुलिस को जंगल का रास्ता दिखाया,
2. एक ने कंपनी को जमीन बेची,
3. तीसरा बस इतना बोला: हमें स्कूल चाहिए।
मैंने तीनों को फाँसी की सजा सुनाई।
कल मेरी बारी होगी, क्योंकि मैंने कोर कमेटी से पूछा था: क्या शिक्षा गद्दारी है?
माँ, तुहारा बेटा अब लाल गमछे में लिपटकर आएगा – पर उस पर खून के धब्बे खाकी रंग के होंगे।
- आपका विशाल
(पूर्व शिक्षक, वर्तमान में 'कॉमरेड ऑग्ज़िलरी' नंबर 307)

विष्णुदेव कैबिनेट विस्तार

प्रशासनिक संवाददाता

छत्तीसगढ़ में बहुप्रतिक्षित कैबिनेट का विस्तार हो गया है। राजभवन में बुधवार की सुबह आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल रमेन डेका ने गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल को मंत्री पद की शपथ दिलाई। तीन नए मंत्रियों के आने से राज्य कैबिनेट में अब सीएम के साथ कुल 14 सदस्य हो गए हैं। भाजपा ने संगठन के बाद सत्ता में भी नए चेहरों को महत्व दिया है। कैबिनेट में शामिल 13 में से 10 पहली बार मंत्री बने हैं। राम विचार नेताम, केदार कश्यप और दयालदास बघेल पहले मंत्री रह चुके हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह प्रदेश पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई थी। संगठन में भी ज्यादातर नए चेहरों को शामिल किया गया है।

कैबिनेट में शामिल किए गए तीनों मंत्री अलग-अलग संभाग से हैं। राजेश अग्रवाल के कैबिनेट में शामिल होने से सरगुजा संभाग का दबदबा बढ़ गया है। कैबिनेट में सीएम समेत सरगुजा संभाग के पांच मंत्री हो गए हैं। इस संभाग की सभी 14 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। बिलासपुर और दुर्ग संभाग से तीन- तीन मंत्री हो गए हैं। वहीं, रायपुर संभाग से कैबिनेट में मंत्रियों की सेंया बढ़कर दो हो गई। वहीं, 12 में से 8 सीट देने वाले बस्तर संभाग से केवल एक मंत्री हैं। भाजपा शासन में ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले डॉ. रमन सिंह की सरकार में बस्तर संभाग से कम से कम दो मंत्री रहते थे।

साय कैबिनेट का जातिगत समीकरण

2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल आबादी में 52 प्रतिशत ओबीसी, 30.60 प्रतिशत एसटी और 12.82 प्रतिशत एससी हैं। साय कैबिनेट में ओबीसी वर्ग के सात मंत्री हैं। एसटी वर्ग के तीन, इनमें सीएम भी शामिल हैं। वहीं, एससी और सामान्य वर्ग के दो-दो मंत्री हैं। प्रतिशत में देखें तो कैबिनेट में 50 प्रतिशत मंत्री ओबीसी हैं। 21 प्रतिशत एसटी, वहीं एससी और सामान्य का प्रतिशत 14-14 है।

प्रदेश के इतिहास में मंत्री बनने वाले गजेंद्र दूसरे यादव

राज्य के इतिहास में यादव समाज से मंत्री बनने वाले गजेंद्र दूसरे विधायक हैं। उनसे पहले डॉ. रमन सिंह सरकार में हेमचंद यादव कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। यह भी संयोग है कि हेमचंद यादव भी दुर्ग सीट से ही चुनाव लड़ते थे।

साय कैबिनेट का क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण

विष्णुदेव साय	सीएम	एसटी	सरगुजा
रामविचार नेताम	मंत्री	एसटी	सरगुजा
केदार कश्यप	मंत्री	एसटी	बस्तर
श्याम बिहारी जायसवाल	मंत्री	ओबीसी	सरगुजा
लक्ष्मी राजवाड़े	मंत्री	ओबीसी	सरगुजा
अरूण साव	डिप्टी सीएम	ओबीसी	बिलासपुर
लखनलाल देवांगन	मंत्री	ओबीसी	बिलासपुर
ओपी चौधरी	मंत्री	ओबीसी	बिलासपुर
गजेंद्र यादव	मंत्री	ओबीसी	दुर्ग
टंकराम वर्मा	मंत्री	ओबीसी	रायपुर
गुरु खुशवंत साहेब	मंत्री	एससी	रायपुर
दयालदास बघेल	मंत्री	एससी	दुर्ग़
राजेश अग्रवाल	मंत्री	सामान्य	सरगुजा
विजय शर्मा	डिप्टी सीएम	सामान्य	दुर्ग

तीनों बड़े नेताओं को हराकर पहली बार बने विधायक

साय कैबिनेट में शामिल किए गए तीनों मंत्री पहली बार के विधायक हैं, लेकिन तीनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं को हराकर सदन में पहुंचे हैं। गजेंद्र यादव ने कांग्रेस के बड़े नेता अरुण वोरा का दुर्ग शहर सीट से मात दी है। गुरु खुशवंत साहेब कांग्रेस सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया को हरा कर विधायक बने हैं। वहीं, राजेश अग्रवाल अंबिकापुर सीट पर टीएस सिंहदेव को पटखनी दी है।

नए के साथ पुराने मंत्रियों को कमान

साव को खेल, परिवहन विभाग कश्यप और आबकारी देवांगन को

विष्णु देव साय	सीएम	सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, जल संसाधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत एवं निवारण एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित न हो।
अरूण साव	डिप्टी सीएम	लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल एवं युवा कल्याण
विजय शर्मा	डिप्टी सीएम	गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
राम विचार नेताम	मंत्री	आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुधन विकास
दयाल दास बघेल	मंत्री	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
केदार कश्यप	मंत्री	वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य
लखन लाल देवांगन	मंत्री	वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर (आबकारी), श्रम
श्याम बिहारी जायसवाल	मंत्री	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन
ओ.पी. चौधरी	मंत्री	वित्त, वाणिज्यिक कर (आबकारी को छोड़कर), आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक
लक्ष्मी राजवाड़े	मंत्री	महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण
टंकराम वर्मा	मंत्री	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, उच्च शिक्षा
गजेन्द्र यादव	मंत्री	स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य
गुरु खुशवंत साहेब	मंत्री	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास
राजेश अग्रवाल	मंत्री	पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व

युवाओं में आशा की 'किरण'

प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी

राजनीतिक संवाददाता

लगभग सात महीने के इंतजार के बाद प्रदेश भाजपा की नई टीम तैयार हो गई है। यह टीम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव की टीम है। सिंहदेव व पार्टी ने युवाओं में आशा जताई गई है। राजनीतिक विश्लेषक इसे नया नेतृत्व तैयार करने की कवायद बता रहे हैं। वजह यह कि 47 लोगों की टीम में एक-दो बड़े नामों को छोड़ दिया जाए, तो अधिकांश नए चेहरे हैं। टीम तैयार करने में इस बात पर खास ध्यान दिया गया है कि गुटबाजों को दूर रखा जाए। सिंहदेव इसी साल 17 जनवरी को दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उसके बाद से ही भाजपा की नई कार्यकारिणीको लेकर कयास लगाए जा रहे थे।

एक भी विधायक को नहीं मिली इंट्री

सिंह देव की इस टीम में आठ उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री, 1 मुख्य प्रवक्ता, 12 प्रवक्ता, 1 कोषाध्यक्ष और एक-एक कार्यालय मंत्री व सह कार्यालय मंत्री बनाए गए हैं। नई टीम में सबसे खास बात यह रही कि सिंहदेव जो खुद विधायक भी हैं, उन्हें छोड़कर एक भी विधायक को इस बार संगठन में जगह नहीं दी गई है।

संगठन की टीम में दो सांसद

नई टीम में दो सांसदों संतोष पाण्डेय को मुख्य प्रवक्ता और रूप कुमारी चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, कोषाध्यक्ष नंदन लाल जैन को अब उपाध्यक्ष बना दिया गया है। उनकी जगह राम गर्ग कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। सिंहदेव ने नई टीम में चार के बजाय 3 महामंत्री बनाए गए हैं। यशवंत जैन, अखिलेश सोनी और नवीन मारकंडे को महामंत्री का प्रभार दिया गया है।

महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व

कार्यकारिणी में इस बार महिलाओं की तादाद ज्यादा है। इनमें रूपकुमारी चौधरी और रंजना साहू को उपाध्यक्ष, संध्या परघनिया, विद्या सिदार, हर्षिता पांडेय और ऋतु चौरसिया को मंत्री बनाया गया है। दो महिलाओं किरण बघेल और शताब्दी पांडेय को प्रवक्ता बनाया गया है। प्रदेश की नई टीम घोषित होने के बाद अब मोर्चा प्रकोष्ठों की नई टीम के लिए कवायद शुरू की जाएगी।
इसके तहत युवा मोर्चा, महिला मोर्चा पर फोकस सबसे ज्यादा रहेगा। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव तक यही टीम काम करेगी इसलिए उन्हें नई टीम तैयार करने के लिए जल्द ही एक्सरसाइज शुरू करने के लिए कहा गया है।

कई नेताओं की छुट्टी

सिंहदेव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मंजूरी के बाद अपनी टीम से कई नेताओं को बाहर कर दिया है। खास तौर पर ऐसे नेताओं को बाहर किया गया है जिनका किसी गुट से नाता था या जो बंगला परिक्रमा में भरोसा रखते थे। इसी प्रकार हाल ही में डीएमएफ का मुद्दा उठाकर विवाद की स्थिति पैदा करने वाले रवि भगत की भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी हो गई है। उनकी जगह राहुल टिकरिहा को भाजयुमो का नया अध्यक्ष बनाया गया है।

क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन

सिंहदेव की नई टीम में ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग सभी को जगह दी गई है। टीम में बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी क्षेत्र के नेताओं को पदाधिकारी बनाया गया है। मोर्चा-प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को भी बदल दिया गया है।

इन्हें मिली कमान

उपाध्यक्ष: रूपकुमारी चौधरी, जगन्नाथ पाणिग्रही, रामजी भारती, रंजना साहू, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, नंदन लाल जैन, जी. वेंकटेश्वर, सतीश लाटिया
महामंत्रीः यशवंत जैन, अखिलेश सोनी और नवीन मारकंडे
मंत्री: संध्या परघनिया, शिवनाथ यादव, जयंती पटेल, अमित साहू, जितेन्द्र कुमार वर्मा, हर्षिता पांडेय, विद्या सिदार, ऋतु चौरसिया
कोषाध्यक्ष: राम गर्ग
कार्यालय प्रभारी: अशोक बजाज
कार्यालय सह प्रभारीः प्रीतेश गांधी
मुख्य प्रवक्ता: संतोष पांडेय
प्रवक्ता: देवलाल ठाकुर, नलिनीश ठोकने, अमित चिमनानी, शिवनारायण पांडेय, प्रमोद कुमार शर्मा, टेकेश्वर जैन, डॉ. विजय शंकर मिश्रा, किरण बघेल, वेदराम जांगड़े, शताब्दी पांडेय, केएल चौहान, उज्ज्वल दीपक।

राहुल योगराज टिकरिहा	प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा
विभा अवस्थी	प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा
अशोक साहू	प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा
आलोक सिंह ठाकुर	प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा
डॉ. सनम जांगड़े	प्रदेश अध्यक्ष अजा मोर्चा
सत्यनारायण सिंह	प्रदेश अध्यक्ष अजजा मोर्चा
मखमूर इकबाल खान	प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा
अवधेश सिंह चंदेल	प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक
चुन्नीलाल साहू	प्रदेश प्रकोष्ठ सह-संयोजक
हेमंत पाणिग्रही	मीडिया संयोजक
मितुल कोठारी	सोशल मीडिया संयोजक
सुनील पिल्लई	आईटी संयोजक

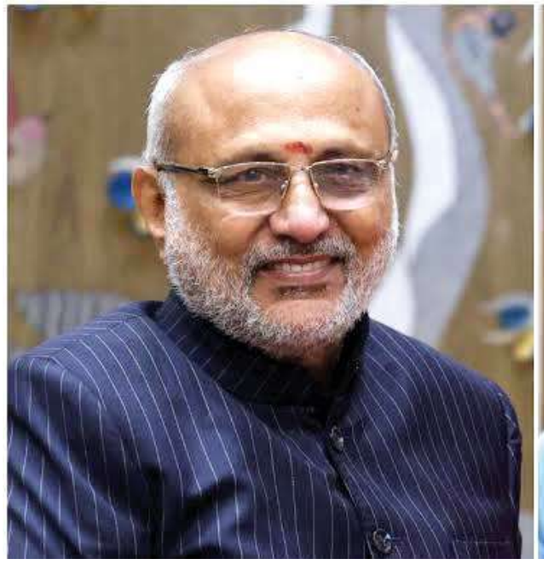

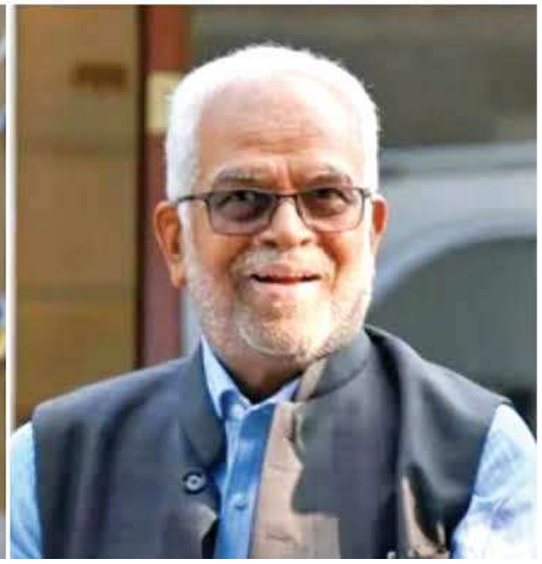

छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई

उपराष्ट्रपति चुनाव : उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त बी. सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई हो गया है। सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज झा समेत भाजपा नेताओं ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा नेता इसे कांग्रेस की देश विरोधी मानसिकता बता रहे हैं।

दरअसल, बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए सलवा जुडूम आंदोलन पर रोक रेड्डी की पीठ ने लगाई थी। सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने इसे आदिवासियों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा बताते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल से पूछा है कि क्या वे इस पर अपत्ति दर्ज कराएंगे। पंकज झा ने कहा कि कांग्रेस ने रेड्डी को केवल इसलिए प्रत्याशी बनाया है क्योंकि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की लड़ाई 'सलवा जुडूम' के विरुद्ध निर्णय देकर छत्तीसगढ़ के मासूम आदिवासियों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। उस समय माओवादियों के विरुद्ध जी-जान से लड़ रहे आदिवासी युवाओं को इसी व्यक्ति के आदेश के कारण रातों-रात निहत्था कर, हमारे वीर युवाओं को मेमना बना कर भूखे भेड़ियों, नक्सलियों के आगे परोस दिया गया था। सबका रोजगार भी छीन लिया गया था। रेड्डी के एक इस निर्णय से 'सलवा जुडूम' जैसे पवित्र आंदोलन को इतनी अधिक क्षति पहुंची, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस आंदोलन के अग्रदूत महेंद्र कर्मा जी की दुखद मृत्यु हुई। कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी उस हमले में दिवंगत हो गई। कितने युवाओं को बाद में चुन-चुन कर माओवादी आतंकियों ने मारा, उसका वर्णन आपको रुला देगा।

....तो आज बस्तर की कुछ और तस्वीर होती: नक्सल हिंसा और आतंक के खिलाफ 2005 में बस्तर के आदिवासी उठ खड़े हुए। नक्सलवाद के खिलाफ उन्होंने बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। आदिवासियों के इस स्वस्फर्त आंदोलन को नाम दिया गया सलवा जुडूम। सलवा जुडूम आंदोलन से राजनीति में आए राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश गागड़ा बताते हैं कि इस आंदोलन की वजह से पहली बार बस्तर में नक्सली बैकफुट पर जाते दिखे, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। ऐसा लगने लगा कि बस्तर में अब लाल आतंक का अंत करीब है, लेकिन तभी सलवा जुडूम पर रोक ला दी गई। यह रोक सुप्रीम कोर्ट के जज के रुप में बी. सुदर्शन रेड्डी की पीठ ने लगाई। इतना ही नहीं कोर्ट ने आदिवासी युवकों के विशेष पुलिस अफसर (एसपीओ) और कोया कमांडों के रुप में भर्ती पर भी रोक लगा दी। सलवा जुडूम पर कोर्ट से रोक लगने के बाद इसमें शामिल रहे दर्जनों आदिवासियों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। गागड़ा कहते हैं कि सलवा जुडूम आंदोलन पर रोक नहीं लगा होता तो आज बस्तर की तस्वीर कुछ और होती।

लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों का ही साथ देती है कांग्रेस : भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने कहा कि उप राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है जिन्होंने जज के रुप में नक्सलवाद के खिलाफ आदिवासियों के स्वस्फूर्त आंदोलन सवला जुडूम पर रोक लगाया था। आदिवासी युवकों के एसपीओ और कोया कमांडों बनने का रास्ता अवरुद्ध किया था। कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए, वह हमेशा देश और लोकतंत्र विरोधी ताकतों का ही साथ देती है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए विपक्ष के पास पर्याप्त बल नहीं है, यह बात कांग्रेस भी अच्छी तरह जान रही है फिर भी उन्होंने प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। होना तो यह चाहिए था कि देश हित में कांग्रेस एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देती ताकि उपराष्ट्रपति जैसे गरिमापूर्ण पद पर निर्विरोध चुनाव होता।

राधाकृष्णन VS सुदर्शन

उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए मतदान तय है। मतदान के लिए 9 सितंबर की तारीख तय है। इस पद के लिए मुकाबला केंद्र में सत्ता रुढ़ एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच होगा। दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं राधाकृष्णन

एनडीए के उप राष्ट्रपति पद के दावेदार बनाए गए सीपी राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। 20 अक्टूबर 1957 को जन्में राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। बीबीए की डिग्रीधारी राधाकृष्णण आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। राधाकृष्णन 1996 से राजनीति में सक्रिय हैं। 96 में उन्हें तमिलनाडु भाजपा का सचिव बनाया गया। 1998 में वे कोयंबटूर सीट से सांसद चुने गए। 2004 में तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए। 2007 तक वे इस पद पर रहे।

2023 में बनाए गए झारखंड के राज्यपाल

सीपी राधाकृष्णन को 2023 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल के साथ पुडुचेरी के उप राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। 2024 में उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं रेड्डी

इंडिया ब्लॉक की तरफ से उप राष्ट्रपति पद के दावेदार बना गए बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज हैं। बीए, एलएलबी तक की शिक्षा प्राप्त सुदर्शन का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। 1971 में उन्होंने हैदराबाद बार काउंसिल में पंजीयन कराया। 1988 में आंध्रप्रदेश के सरकारी वकील बने। 1995 में उन्हें आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया। 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे।

ज्ञान विज्ञान और अनवरत श्रम विकसित राष्ट्र की बुनियाद

संजीव ठाकुर

वैश्विक परिदृश्य में किसी भी देश की पहचान और उसका महत्व देश की शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता,संस्कारों में अंतर्निहित ज्ञान और देश की सांस्कृतिक विविधता से ही होती है। इसके पश्चात प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एवं विज्ञान, तकनीकी एवं व्यापारिक क्षमता से देश की स्थिति का आकलन होता है।

किसी भी राष्ट्र की आधारशिला उस राष्ट्र की संस्कृति, शिक्षा, संस्कार और ज्ञान की कसौटी ही होते है। शिक्षित नागरिक ही महान राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और संस्कृति,संस्कार उसे समृद्ध देश बनाते हैं। राष्ट्र निर्माण में हर नागरिक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज का नवजात शिशु कल का सफल नागरिक होता है, उसकी शिक्षा-दीक्षा और संस्कार से ही देश की सफलता निर्भर होती है। कक्षा की पिछली सीट पर बैठे किसी आइंस्टीन की तलाश के लिए पारखी की नजरों की आवश्यकता होती है। जिसे नकारा घोषित कर विद्यालय से निकाल दिया जाता है, वही बालक आगे चलकर युग परिवर्तनकारी "सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत" दे जाता है. न्यूटन के गति के सिद्धांत हमारे जिंदगी को द्रुतगति से आगे की ओर अग्रसर करते हैं। यह ऐसे बालक जो जो आगे चलकर बनी बनाई परंपरा तथा लीक से हटकर चलते हैं, और परंपराओं पर गहरी चोट करते हैं। जो समाज से सुना, उसे सुनकर रह नहीं जाते हैं, और जो समाज में उसने देखा,सिर्फ देख कर नहीं रह जाते हैं, बल्कि देख सुनकर उस पर चिंतन मनन कर नई धारणा तथा सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं और विश्व को उसकी सौगात भी देते हैं। हमें इन महान बालकों को गरीब बस्तियों से लेकर गली मोहल्ले और शहरों में खोजना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलीन कि अपनी राय है कि बिना वैचारिक स्वतंत्रता के बुद्धि जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। हम वर्तमान में जिस समाज में हैं और जिस समाज से हमने सेयता का विकास की शुरुआत की है, उसका जब सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो यही पाते हैं कि अपनी आजादी के तमाम तामझाम बनाने वाला इंसान दिन प्रतिदिन अपनी की बनाई दुनिया के बोझ तले गुलाम होता जा रहा है।

आज हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है, कि बचपना बस्ते के बोझ तले दबता चला जा रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को किताबी कीड़ा बनाने के बजाय उसकी नैसर्गिक रचनात्मक प्रतिभा को उभार कर जीवन उपयोगी बनाएं। बच्चों का मूल्यांकन सिर्फ इसी आधार पर नहीं होना चाहिए कि उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि उसकी रूचि किस क्षेत्र में ज्यादा है, और वह जीवन में इस क्षेत्र में आगे बढ़ कर एक सफल इंसान और समाज के लिए कितना उपयोगी हो सकता है,और वह खेल, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान में कितना अपनी शक्ति और क्षमता के हिसाब से क्या प्रदर्शन कर सकता है। माता-पिता तथा अभिभावकों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसे जबरिया डॉक्टर,इंजीनियर, वैज्ञानिक या अधिकारी बनाने की बजाय उसकी रूचि हो को मद्देनजर रखकर उसका कैरियर चुनने की आजादी देने में मदद करनी चाहिए।

अधिकांश भारतीयों ने जो अनुसंधान या नई खोजें की हैं, वह सब विदेशों में जाकर ही वहीं की सुविधाएं प्राप्त कर,परिणाम दे सके हैं। भारत में गणित, विज्ञान तकनीकी संचार,इंजीनियरिंग, मीडिया रिसर्च की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यह अत्यंत विचार योग्य है कि हम अपने युवा देश के युवा साथियों को उत्कृष्ट मंच अनुसंधान अथवा साहित्य, संस्कृति,विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में नहीं दे पा रहे हैं।

प्रतिभा पलायन की दरों में वृद्धि को रोककर हमें अपने बच्चों को बाल्यकाल से उनकी विचारधारा तथा रूचि के अनुसार समस्त सुविधाएं प्रदान कर नई चीजों के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर उन्हें साधन संपन्न बनाना चाहिए।

हमारी शिक्षा नीति हमारे अभिभावक, समाज और सरकार को चाहिए कि बचपन से सृजन क्षमता को आगे बढ़ाकर जिंदगी के बहुत से पाठ स्वयं सीख कर उनके उत्तर तलाशने में उन्हें सक्षम बनाएं। यह एक प्रकार का मनोविज्ञान भी है। यह मनोविज्ञान माता,पिता, भाई, बहन एवं बालक को समझ में आए ऐसा उनके बाल काल से ही व्यवहार के रूप में समझाना होगा, तब जाकर वह छोटा बालक एक विचार वान देश और समाज के उपयोगी नौजवान बन पाएगा। दार्शनिक रूसो ने भी कहा है कि "मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता परंतु सामाजिक बंधनों द्वारा जकड़ लिया जाता है" जरूरी है कि बालकों बालिकाओं के बाल काल से ही बंधनों से स्वतंत्र रखा जाए अतिवादीता तथा रूढ़विादिता से परे उन्हें स्वतंत्र विचार करने की मौलिकता तथा क्षमता को विकसित होने की प्रक्रिया में अनुसरण करने का मौका दिया जाए। इससे हम जिस लोक में जी रहे हैं उस समाज को नए रूप में वक्त के साथ बदला जा सके। वैसे देखा जाए तो हम जिस पूंजीवादी बाजार वादी व्यवस्था में सांस ले रहे हैं, वहां हम एक निजी स्वार्थी व्यक्तित्व का निर्माण करने में व्यस्त हैं ।आज के युग में हर युवा आगे बढ़ने की ललक में वस्तुओं का सृजन करने की बजाय सब कुछ रेडीमेड लेने की व्यवस्था का अनुगामी बन गया है। इस तरह हमारे समाज की विचारधारा तथा बुद्धि भी रेडीमेड हो चुकी है। इस तरह हम अंकुरित होते पौधे को ज्यादा से ज्यादा खाद बीज डालकर एक खोखला तथा आधारहीन कमजोर वृक्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमें दिशाहीन अंधेरे की तरफ ले जा रहा है, एवं हमारी समूची युवा अपनी की वैचारिकता को दीमक लगाने जैसा काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के विद्यालय में यह दृश्य आम दिखाई देता है कि बच्चे कलम दवात की बजाए थाली और कटोरी लेकर मिड डे मील के लिए आते हैं, निसंदेह यह गरीबी के कारण होता है, पर है तो दुर्भाग्य। मिड डे मील के कारण स्कूल में बच्चों की उपस्थिति दुगनी हो जाती है। किसी ने यह भी सच कहा है कि "विचारों का रास्ता पेट से होकर गुजरता है" गरीबी ने देश के होनहार बच्चों की वैचारिक क्षमता को कलम थाली और ग्लास में समेट कर रख दिया है।

स्वतंत्र विचारों को बचपन से प्रोत्साहित करने के उपायों में एक प्रमुख उपाय गरीबी दूर करना तो है ही, बाल श्रम को भी हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे बच्चा स्कूल से दूर होकर अपने पेट भरने तक सीमित रह जाता है। दूसरे क्रम में विचारधारा को विकसित करने के लिए अच्छे और विद्वान शिक्षकों की स्कूलों में नियुक्ति की जानी चाहिए। क्योंकि शिक्षक ही मां बाप के पश्चात बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित करने वाला एक आधार स्तंभ होता है। एक तरफ बाल मनोविज्ञान को समझकर बाल काल से ही बच्चों को वैचारिक क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि हम देश को विद्वान, साहित्यकार,वैज्ञानिक अधिकारी,डॉक्टर और इंजीनियर दे सकें।

(लेखक
वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक लेखक, चिंतक
स्तंभकार, रायपुर छत्तीसगढ़)

रायपुर में अब पुलिस कमिश्नर

एडीजी या आईजी रैंक के अफसर की होगी पोस्टिंग

संभाग आयुक्त और कलेक्टरों का घट जाएगा पावर

विशेष संवाददाता

राजधानी रायपुर अब पुलिस कमिश्नरी बनेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की। पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में सीएम साय यह ऐलान किया। कमिश्नरी सिस्टम में एडीजी या आईजी रैंक के अफसर की पुलिस कमिश्नर के रुप में पदस्थापना होगी। इसके साथ ही पुलिस अफसरों के पदनाम भी बदल जाएंगे। कमिश्नर की पदस्थापना के साथ ही संभाग आयुक्त और कलेक्टर के हाथ से कानून-व्यवस्था से जुड़ी शक्तियों वापस ले ली जाएगी। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम देश के कुछ महानगरों में लागू है।

पुलिस कमिश्नर की शक्तियां

पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू होने से कानून-व्यवस्था से जुड़ी कई शक्तियां पुलिस के पास आ जाएगी। प्रतिबंधात्मक धाराओं में होने वाल कार्यावाही में आरोपियों की पेशी कमिश्नर की कोर्ट में होगी। धारा 144 और कर्फ्यू लगाने का फैसला भी कमिश्नर लेंगे। जिलाबदर, आर्म्स एक्ट में कार्यवाही से लेकर बड़े सर्वाजनिक आयोजन का फैसला भी कमिश्नर के जरिये होगा। इससे पुलिस को फैसले लेने में आसानी होगी। अभी ये सभी काम जिलों में कलेक्टर करते हैं।

देश के इन जिलों में लागू है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम

पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पहले से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर जैसे बड़े महा नगरों में लागू है। इसमें शहर की कमान किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को दी जाती है। कौन-सा अधिकारी बैठेगा, यह राज्य सरकार तय करती है और यह शहर की आबादी व क्राइम रिकॉर्ड पर निर्भर करता है।

सीमित हो जाएंगे कलेक्टर के अधिकार

पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति से कलेक्टर के अधिकार सीमित हो जाएंगे। कलेक्टर केवल राजस्व से जुड़े मामले ही देखेंगे। कानून-व्यवस्था से जुड़ी सभी शक्तियां कमिश्नर के पास चली जाएगी।

अफसरों का बदल जाएगा पदनाम

कमिश्नरी सिस्टम में पुलिस अफसरों के पद नाम बदल जाएंगे। डीआईजी या एसएसपी रैंक के अफसर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कह लाएंगे। एडिशनल एसपी सहायक आयुक्त हो जाएंगे।

महंगाई से राहत की आस

इन पर लगे पांच प्रतिशत जीएसटी तो बनेगी बात

दो टैक्स स्लैब और एक स्पेशल टैक्स स्लैब की चर्चा

वाणिज्य संवादाता

महंगाई की मार झेल रहे लोगों को दीपावली से राहत मिलने की आस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में बदलाव का ऐलान किया है। इसे देखते हुए आने वाले दिनों में आम उपभोक्ताओं को उनकी दैनिक जरूरतवाली सामग्रियों की बढ़ती कीमतों से थोड़ी राहत मिल सकती है।

इनमें भी मिले राहत तो क्या कहना

उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, सीमेंट, परफ्यूम, शैंपू, मेकअप, पटाखे, मेकअप का सामान और मोटरसाइकल पर वर्तमान में 28 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। दोपहिया तो सभी की मुख्य जरूरत बन चुकी है,ऐसे में काफी समय से दोपहिया में जीएसटी का स्लैब कम करने की मांग की जा रही है। आटोमोबाइल कारोबारियों का कहना है कि दोपहिया में 18 प्रतिशत जीएसटी ही लगना चाहिए।

उपभोक्ताओं को इतनी मिल सकती है राहत

ऐसे समझे- मान लीजिए आप एक बाइक लेते है,28 फीसद जीएसटी मिलाकर इसकी आन रोड कीमत पहुंचती है एक लाख रुपए। अगर दोपहिया में जीएसटी 18 प्रतिशत हो जाता है तो सीधे आपकी दोपहिया की कीमत में 10 प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। इसी प्रकार दूध को देखा जाए तो अभी आपको आधा लीटर दूध 12 फीसद जीएसटी के साथ 29 रुपए में मिलता है। अगर इस पर जीएसटी पांच फीसद हो जाता है तो यह दूध आपको लगभग 27 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। इसी प्रकार अन्य उपयोगी है।

रोजमर्रा की इन वस्तुओं में राहत की आस

संभावना जताई जा रही है कि सूखा मेवा, दूध, फ्रोजन सब्जियां, टूथ पाउडर, साइकिल, फर्नीचर,हैंड बैग, पेंसिल आदि पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाया जा सकता है। वर्तमान में इन सामग्रियों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

कारोबारियों को प्रधानमंत्री पर भरोसा

वित्त मंत्रालय ने दो टैक्स स्लैब व एक स्पेशल टैक्स स्लैब की सिफारिश ग्रुप आफ मिनिस्टर्स को भेज दिया है। अनाज कारोबारी मनीष राठौड़ कहते हैं कि जीएसटी में राहत से फायदा मिलेगा। कई सामग्रियां, जो दैनिक उपयोगी होने के बाद भी ज्यादा जीएसटी लग रहा है।

यह हो सकता है बदलाव

जानकारों के अनुसार जीएसटी में यह बदलाव हो सकता है कि जिन सामग्रियों में 12 प्रतिशत का जीएसटी लग रहा है,उन्हें पांच प्रतिशत के जीएसटी स्लैब में लाया जाएगा। साथ ही जिन सामग्रियों में 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है,उन सामानों में 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही तंबाकू, सिगरेट, बीयर आदि पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाने की चर्चा है।

ये भी हो सकते है सस्ते

जानकारों का कहना है कि आम जरूरत के उत्पाद भी सस्ते हो सकते है। इनमें ग्रॉसरी, दवाईयां, टेलीविजन, वाशिंग मशीन आदि शामिल है। इसके साथ ही खेती उपकरण, साइकिल, इंश्योरेंस व पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी सेवाओं पर लगने वाला जीएसटी कम हो सकता है। संभावना है कि पांच प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 40 प्रतिशत का जीएसटी स्लैब हो सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधार पर विचार विर्मश कर रहे मंत्रियों के समूह को प्रस्ताव भेज दिया है। यह ग्रुप इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर जीएसटी काउंसिल के सामने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

एसईसीएल के सीएमडी हरीश दुहन ने दिलाई सत्यनिष्ठा की शपथ

एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर में केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तीन माह के निवारक सतर्कता अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सीएमडी एसईसीएल हरीश दुहन ने सभी उपस्थितों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानन्द उपस्थित थे। कार्यक्रम में सुनील जैन, आयुक्त, बिलासपुर संभाग एसईसीएल निदेशक (तकनीकी-संचालन सह योजना/परियोजना एन. फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास और मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन की विशिष्ट उपस्थिति रहे।

मुख्य अतिथि पी. दयानन्द ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में चाहे पीएसयू हों या राज्य शासन, पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से सतर्कता एवं पारदर्शी कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य शासन दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं तथा क्षेत्र के विकास के लिए दोनों के बीच परस्पर सहयोग एवं समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन ने बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस वर्ष के अभियान की थीम सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। इस अभियान के पांच प्रमुख बिंदु हैं -लंबित शिकायतों का निपटान, लंबित मामलों का निपटान, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन, संपत्तियों का प्रभावी प्रबंधन तथा डिजिटल पहलों को बढ़ावा देकर कार्यप्रणाली को और अधिक आधुनिक एवं पारदर्शी बनाना।

सतर्कता विभाग द्वारा एसईसीएल में कार्यसंचालन को बेहतर बनाने हेतु कई प्रयास किए गए हैं। जैसे कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए थर्ड पार्टी टेस्टिंग, सीसीटीवी निगरानी और रियल टाइम सुपरविजन से पारदर्शी प्रणाली का विकास। खरीद प्रक्रियाओं में एसओपी आधारित बिल प्रोसेसिंग, एफआईएफओ क्लियरेंस और एसएपी आधारित ट्रैकिंग लागू की गई है। संपत्ति प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए मशीनों का सत्यापन और डिजिटल टैगिंग की गई है। जटायु डैशबोर्ड, डिजीकोल और इंटेग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संचालन एवं निगरानी को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया गया है।

कार्यक्रम में महाप्रबंधक (सतर्कता) नागेश्वर राव सहित मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्षगण, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

जो भी करें नियत और नीति के दायरे में रह कर करें: दुहन

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एसईसीएल सीएमडी हरीश दुहन ने कहा कि मैं टीम एसईसीएल के प्रत्येक सदस्य से यह आह्वान करना चाहता हूँ कि हम जो भी कार्य करें, नियम एवं नीति के दायरे में रहकर पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करें।

राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि एसईसीएल को अपने कार्यसंचालन को बेहतर बनाने के लिए राज्य शासन से निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होता रहता है। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष हम मेगा प्रोजेक्ट्स में भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया में गति ला पाए हैं। इस दौरान उन्होंने भू-अधिग्रहण एवं अन्य क्षेत्रों में राज्य शासन से वांछित सहयोग से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की।

नवा रायपुर में क्रिकेट एकेडमी

छत्तीसगढ़ सरकार ने दी 7.96 एकड़ भूमि

छत्तीसगढ़ के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-3, ग्राम-परसदा में 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट एकेडमी की स्थापना के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि सरकारी व्ययन नियमों के तहत, गैर-लाभकारी संस्थाओं को सीधे भूमि आवंटन का प्रावधान नहीं है, लेकिन इस विशेष मामले में राज्य शासन ने नियमों को शिथिल कर यह निर्णय लिया है, जिससे खिलाड़ियों के हित में क्रिकेट एकेडमी की स्थापना हो सके।

कुल 7.96 एकड़ जमीन की है पहचान

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को 2016 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से पूर्णकालिक मान्यता प्राप्त है। एकेडमी के लिए नवा रायपुर विकास प्राधिकरण ने 7.96 एकड़ भूमि चिन्हित की है।

अपनी प्रतिभा से पहचान बना रहे राज्य के खिलाड़ी

छत्तीसगढ़ राज्य में क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मौजूद है, परंतु अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं और प्रशिक्षण के लिए एकेडमी की जरूरत महसूस की जा रही थी।

मिलेगी विशेष पहचान

इस निर्णय से प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को क्रिकेट में आगे बढ़ाने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे और राज्य को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम न केवल प्रदेश के युवा क्रिकेटरों के लिए अवसर के नए द्वार खोलेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को खेल के क्षेत्र में मजबूत पहचान दिलाने में सहायक होगा।

अनिता मंदिलवार सपना

रीना के बेटे ने आज ऐसे खुशखबरी दी थी कि रीना के पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। मारे खुशी के आज तो नींद भी नहीं आ रही थी। रीना के गले में उसका बेटा रोहित बाहें डालकर कहा था मुझे आपको कुछ बताना है माँ और यह कहते हुए उसका गोरा चेहरा शर्म से गुलाबी हो आया था।

अच्छा तो तुझे मेरी बहू मिल गई लगता है रीना ने कहा।

मां अगर आप उसे स्वीकार करेगी तब।

रोहित बेटा तुम तो जानते हो तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। बताओ तो कौन है वह जिसने मेरे बेटे के दिल में जगह बना ली है। बेटे के हाथों को प्यार से अपने हाथों में लेते हुए रीना ने कहा।

माँ, रेखा नाम है उसका मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ाई की है हम लगभग सात साल से एक दूसरे को जानते हैं और पसंद करते हैं।

अच्छा तो कब मिलवा रहे हो मेरी बहू से?

माँ, कल बुला लूँ नाश्ते पर ।

हाँ जरूर अब जाओ सो जाओ ।

रीना सुबह उठकर बहू का स्वागत करने के लिए

अच्छी-अच्छी व्यंजन बना डाली और रसोई से पकवानों की खुशबू आने लगी। रोहित ने उठने के साथ ही रसोई की तरफ झांककर कहा - माँ इतनी खुशबू रसोई से आ रही है। क्या बना रही हैं?

रोहित मेरी बहू घर पहली बार आ रही है तो क्यों ना बनाऊं। बताओ रसोई का काम निपटाकर अच्छे से तैयार हुई रीना बहुत समय बाद आईने में अपने आप को देखने लगी।

माँ आज आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं अच्छा तो आप बहू के लिए तैयार हुई हैं।

हाँ, घंटी बजी है लगता है रेखा आ गई है और जैसे ही दरवाजा खोला तो रेखा सुंदर सी गुलाबी साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। आओ अंदर उसने रेखा का हाथ पकड़ कर अंदर की ओर इशारा किया। जैसे ही रेखा पर रीना की नजर पड़ी वह तो हतप्रभ रह गई । वही हालत रेखा के भी थे। दोनों ने कभी सोचा न था कि इस तरह मुलाकात होगी। उसे चक्कर सा आ गया और रोहित ने पड़कर सोफे पर रीना को बिठाया।

क्या हो गया माँ आपको अचानक?

कुछ नहीं बेटा मैं ठीक हूँ।

ठीक है माँ! आप आराम कीजिए मैं चाय बना कर लाता हूँ ।

इस समय देखा और रीना को एकांत मिला और रेखा बोलने लगी आंटी सॉरी मुझे पता नहीं था कि रोहित आपका बेटा है और आंखों से आँसू बरसने लगी थी।

सुनो रेखा! मेरे पास आओ तुझे देखकर अतीत की सारी बातें स्मरण हो आई हैं जब तुम मुझे घायल अवस्था में सड़क पर मिली थी। कुछ दरिंदे ने तुम्हारे साथ गलत किया था मैं आनन-फानन में अस्पताल लेकर गई और इलाज कराया। तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी अब मुझे नहीं जीना। बाद में तुम ठीक हो गई और मुझसे संपर्क में भी रही। मैंने तब कहा कि तुम अब बड़ी हो रही हो अब पढ़ाई में ध्यान दो और उस घटना को भूल जाओ।

आंटी मैं रोहित से शादी नहीं कर सकती।

देखो रेखा! जो हुआ उसमें गलती नहीं थी तुम इतनी प्यारी बच्ची हो मेरे बेटे की खुशियाँ तुम संग हैं। बस एक वादा तुमसे चाहिए तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। रोहित से भी बताने की जरूरत नहीं है।

पर आंटी, रोहित से छुपाना क्या ठीक होगा।

आंटी आप बहुत महान है भावुक होकर रीना के गले लग गई गई। रीना ने रेखा से कहा कि देखो बेटा हमारा बुरा वक्त हमारे जीवन को नई दिशा दे जाता है। इसे नहीं भूलना चाहिए। कल ही अपनी मां पापा को शादी की बात करने के लिए भेज देना। रेखा और रोहित दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए।

(व्याख्याता, साहित्यकार
अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़)

VLF Mobster

खास फीचर्स और दमदार डिजाइन के साथ 25 सितंबर को होगा लांच

Motohaus जल्द ही भारत में 25 सितंबर 2025 को अपना नया पेट्रोल स्कूटर VLF Mobster लांच करेगा। यह कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट और पहला पेट्रोल स्कूटर है, जो खासकर युवाओं के लिए मस्कुलर डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स के साथ तैयार किया गया है।

मस्कुलर और बोल्ड डिजाइन VLF Mobster का डिजाइन बाकी स्कूटरों से अलग और काफी बोल्ड है। इसमें ट्विन-हेडलैंप फ्रंट पैनल है, जो इसे खास बनाता है। चौड़ा हैंडलबार और अलग साइड पैनल इसे स्ट्रीट बाइक जैसा लुक देते हैं। इसकी सिंगल-पीस सीट आरामदायक है और बॉडी मजबूत है। यह डिजाइन खासतौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे यह शहर में चलाने के लिए बढ़िया विकल्प होगा।

मॉडर्न तकनीक और प्रीमियम फीचर्स VLF Mobster स्कूटर में 5-इंच का डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा, जो मोबाइल स्क्रीन को कनेक्ट कर सकता है। इसमें स्क्रचार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है ताकि आप चलते-फिरते अपने फोन को चार्ज कर सकें। स्कूटर में डुअल-चैनल ABS लगे हैं, जो ब्रेकिंग को ज्यादा सुरक्षित बनाते हैं। साथ ही, इसमें लाइव डैशकैम का भी ऑप्शन होगा, जो ड्राइविंग के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करेगा और सुरक्षा बढ़ाएगा। ये सभी फीचर्स इसे उपयोग में आसान और भरोसेमंद बनाते हैं।

इंजन पावर और ड्राइविंग अनुभव VLF Mobster स्कूटर में दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे, एक 125cc और दूसरा 180cc । 125cc इंजन लगभग 12 bhp पावर और 11.7 Nm टॉर्क प्रदान करता है। वहीं 180cc वाला इंजन ज्यादा पावर देता है। यह 18 bhp की पावर और 15.7 Nm टॉर्क प्रदान करता है। दोनों इंजन शहर में आसानी से ड्राइव करने के लिए अच्छे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। Iso Read - Suzuki Wagon R ने दुनियाभर में 1 करोड़ यूनिट्स की बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ा, भारत में भी मशहूर! बेहतरीन रोड ग्रिप और स्टेबिलिटीVLF Mobster स्कूटर में 12-इंच के मजबूत एलॉय व्हील्स लगे हैं। इसके फ्रंट टायर की चौड़ाई 120 सेक्शन और रियर टायर की 130 सेक्शन है, जो सड़क पर बेहतर पकड़ और स्थिरता देते हैं। साथ ही, इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, जो खराब रास्तों पर भी आराम देने वाला सफर सुनिश्चित करते हैं।रंग विकल्प जो युवाओं को पसंद आएंगेVLF Mobster स्कूटर कई आकर्षक रंगों में लॉन्च होगा। इसमें ग्रे, सफेद, लाल और पीला रंग शामिल हैं। ये रंग स्कूटर को अलग पहचान देते हैं और खासकर युवाओं के बीच लोकप्रिय होंगे। हर रंग में स्कूटर का स्टाइल और आकर्षण बढ़ जाता है, जो शहर की सड़कों पर ध्यान आकर्षित करेगा।

बाल गीत - बादल बरसे

बादल बरसे जब थम थमकर।
बिजली चमके नभ में जमकर।
बादल बरसे जब थम थमकर.....

बूँदें चाँदी टपके टप-टप, हर्षित होते सूखे पादप,
ताल-तलैया तोड़े निज तट, गाय, बैल सब भागे सरपट।
करे हवा भी बातें सर-सर, बादल बरसे जब थम-थमकर।-1

सुन किसान की बोली हर्र-हर्र, मेंढक भी करता अति टर्र-टर्र,
धरती धानी ओढ़े हरियाली, कण-कण में बिखरी खुशहाली।
वृंदगान करते हैं नभचर, बादल बरसे जब थम-थमकर।-2

मेघराग चुप सुनलो छम-छम, सौंधी माटी का भी दम-खम,
पानी पाकर पसरे आँगन, फूला नहीं समाए सावन।
मौसम हुआ सुहाना मनहर, बादल बरसे जब थम-थमकर।-3

चलो चलाएँ कागज कश्ती, छप-छप पानी, करने मस्ती,
पाँव-पाँव तक लथपथ कीचड़, दादी कहती बाहर अंधड़।
बैठ पकौड़े खाओ घर पर, बादल बरसे जब थम थमकर।-4

बादल बरसे जब थम थमकर।
बिजली चमके नभ में जमकर।
बादल बरसे जब थम थमकर.....

कन्हैया साहू (अमित)
भाटापारा छत्तीसगढ़

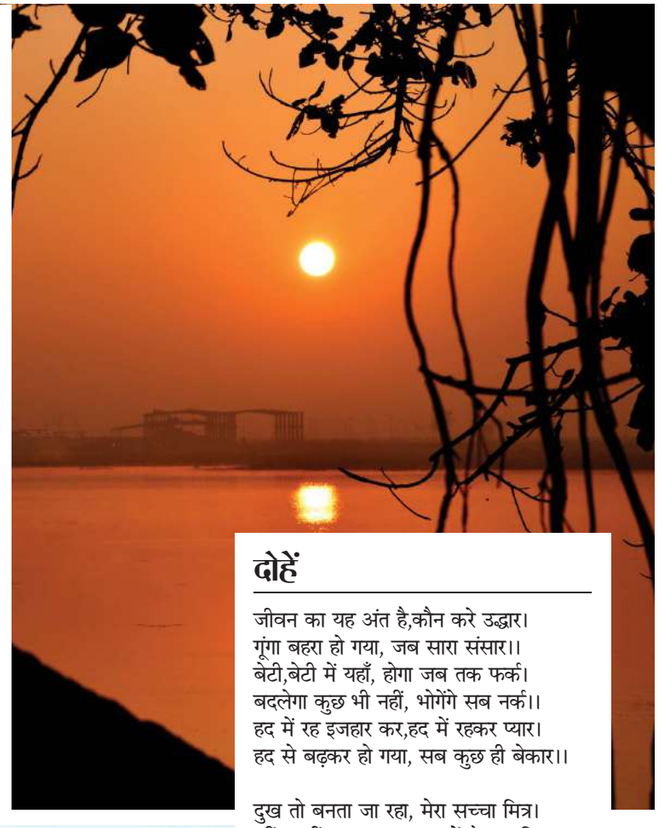

दोहें

जीवन का यह अंत है,कौन करे उद्धार।
गूंगा बहरा हो गया, जब सारा संसार।।
बेटी,बेटी में यहाँ, होगा जब तक फर्क।
बदलेगा कुछ भी नहीं, भोगेंगे सब नर्क।।
हद में रह इजहार कर,हद में रहकर प्यार।
हद से बढ़कर हो गया, सब कुछ ही बेकार।।

दुख तो बनता जा रहा, मेरा सच्चा मित्र।
खींच-खींच कर ला रहा,यादों के चलचित्र।।

माना मेरी जिंदगी, कष्टों का अंबार।
जीने से फिर भी मुझे, बहुत अधिक है प्यार।।

सुबह दोपहर शाम में, ज्यों ढलती है धूप।
धीरे-धीरे घट रहा, त्यों मानव का रूप।।

जीवन में हर लक्ष्य को, पा सकते हैं आप।
हर पल जब जीते रहें, कर सपनों का जाप ।।

सुख सुविधाओं के हुए,हम सब इतने दास।
पलभर भी इनके बिना,जीवन है संत्रास ।।

रोना-धोना कर दिया खुद से इतना दूर।
दौड़-दौड़ आने लगीं, खुशियाँ हो मजबूर।।

अकड़-अकड़कर चल रहे,सबके सब नादान।
संस्कारी चिड़िया नहीं, बैठी जिस दालान।।

राजा के दरबार का,गजब हुआ है हाल।
सच्चा डर से कांपता,झूठा खाए माल।।

सोनिया वर्मा, रायपुर

कलियुग है

कलयुग है ! पत्थर जवाहिर हो गए
इंसानियत सीखी, काफिर हो गए
हमने एक दो शेर क्या, अच्छे लिखे
ऐसी अकड़ जैसे, साहिर हो गए

यूँ ही दिल हमें ना भेजा कीजिये
दिल की बेकद्री में, माहिर हो गए

दुनियावी इश्क से, दूर हुए तभी
नजरों में खुदा की वो, ताहिर हो गए

जबसे खुद से ही, प्यार हुआ है हमें
दुनिया की नजर में, आखिर हो गए

रब की निगहबानी में, जब से रमें
रोएँ रोएँ से हम, जाकिर हो गए

मुश्किल राज कैसे, दिल में ही छुपें
लब से या नजर से, जाहिर हो गए।

सीमा कौशिक (मुक्त), फरीदाबाद

व्रत त्योहार सितंबर 2025

3 सितंबर 2025 - परिवर्तिनी एकादशी
4 सितंबर 2025 - वामन जयंती
5 सितंबर 2025 - ओणम, प्रदोष व्रत
6 सितंबर 2025 - गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी
7 सितंबर 2025 - भाद्रपद पूर्णिमा व्रत, चंद्र ग्रहण
8 सितंबर 2025 - पितृ पक्ष शुरू
10 सितंबर 2025 - विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी
14 सितंबर 2025 - जीवित्पुत्रिका व्रत
17 सितंबर 2025 - एकादशी श्राद्ध, इंदिरा एकादशी, कन्या संक्रांति
18 सितंबर 2025 - गुरु पुष्य योग
19 सितंबर 2025 - मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत
21 सितंबर 2025 - सर्व पितृ अमावस्या
22 सितंबर 2025 - शारदीय नवरात्रि शुरू, घटस्थापना
25 सितंबर 2025 - विनायक चतुर्थी

छत्तीसगढ़ में शासकीय अवकाश

सार्वजनिक अवकाश	
6 सितंबर	ईद-मिलाद उन नबी
	ऐच्छिक अवकाश
3 सितंबर	ढोल एकादश
5 सितंबर	ओणम
6 सितंबर	अनंत चतुर्दशी
17 सितंबर	विश्वकर्मा जयंती
20 सितंबर	प्राण नाथ जयंती
21 सितंबर	सर्व पितृमोक्ष अमावस्या
22 सितंबर	अग्रसेन जयंती
30 सितंबर	दशहरा

सितंबर में रिलीज होने वाली फिल्में

बागी 4
5 सितंबर को टाइगर श्रॉफ की यह एक्शन फिल्म रिलीज होगी, जिसमें संजय दत्त विलेन के रूप में होंगे।

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी।
12 सितंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी है।

जॉली एलएलबी 3
19 सितंबर को अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर यह फिल्म रिलीज होगी।

द बंगाल फाइल्स।
5 सितंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म में विवेक अग्निहोत्री की खास झलक देखने को मिलेगी।

भेड़िया 2
31 अगस्त को रिलीज होने वाली यह फिल्म भी सितंबर के शुरू में रिलीज होगी। इसमें वरुण धवन और कृति सेनन लीड रोल में हैं।

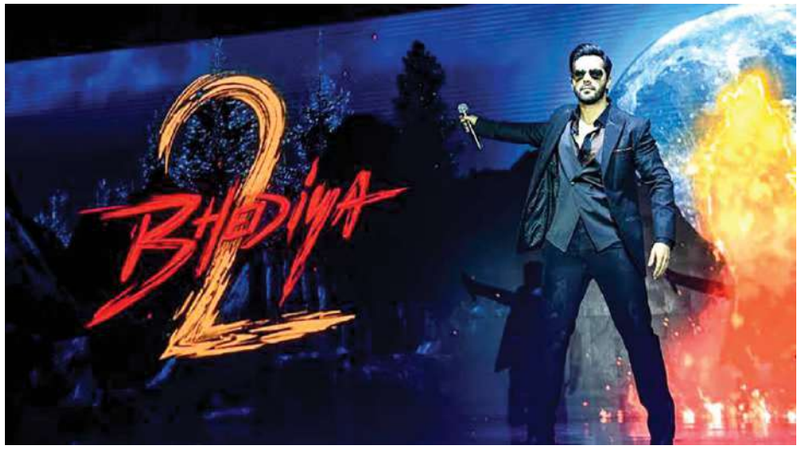

ओटीटी पर इस महीने

रिलीज़ की तारीख	शीर्षक	प्लैटफ़ॉर्म
5 सितंबर, 2025	इंस्पेक्टर ज़ेंडे	NetFlix
9 सितंबर, 2025	केवल बिल्डिंग में हत्याएं सीजन 4	जियो हॉटस्टार
17 सितंबर, 2025	जनरेशन V सीज़न 2	अमेजॉन प्राइम
24 सितंबर, 2025	होटल कोस्टिएरा सीज़न 1	अमेजॉन प्राइम

अब बिना अकाउंट के भी वाट्सएप पर कर सकेंगे बातचीत

WhatsApp ने 2025 में यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई नए और बड़े बदलाव किए हैं। अब ऐप में चैटिंग, कॉलिंग और ग्रुप इंटरैक्शन पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया है। इस साल वाट्सएप ने कुल चार बड़े अपडेट पेश किए हैं, जिनमें दर्जनों नए फीचर्स शामिल हैं। खास बात यह है कि अब वाट्सएप ऐसे लोगों से भी चैट की सुविधा देने जा रहा है जिनके पास वाट्सएप अकाउंट ही नहीं है। वाट्सएप का यह बदलाव न केवल तकनीकी रूप से नया है, बल्कि इससे ऐप की पहुंच भी और अधिक लोगों तक बढ़ेगी। इसके अलावा ग्रुप कॉल, चैट रिएक्शन, वॉइस नोट ट्रांसक्रिप्शन, और यूजर्स की सुरक्षा को लेकर भी कई नई सुविधाएं जोड़ी गई है।

अब बिना अकाउंट चैट भी संभव

वाट्सएप एक नया गेस्ट चैट फीचर टेस्ट कर रहा है जिससे वाट्सएप यूजर्स ऐसे लोगों से भी बातचीत कर सकेंगे जिनका वाट्सएप अकाउंट नहीं है। यह सुविधा फिलहाल वाट्सएप Beta for Android के वर्जन 2.25.22.13 में देखी गई है। इस फीचर के तहत यूजर्स एक चैट लिंक SMS, ईमेल या सोशल मीडिया के जरिये भेज सकते हैं और रिसीवर बिना ऐप इंस्टॉल किए भी चैट कर सकेगा।

गेस्ट चैट की लिमिट क्या हैं

इस नए फीचर में कुछ लिमिट भी रखी गई हैं. जो लोग गेस्ट मोड में वाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे, वे केवल टेक्स्ट चैट कर सकेंगे. वे मीडिया फाइल्स, तद्भव, वॉइस मैसेज भेजने या वीडियो कॉल करने में सक्षम नहीं होंगे। यह पूरी तरह वाट्सएप के अपने वेब इकोसिस्टम पर आधारित होगा।

ग्रुप कॉल और चैट अनुभव में सुधार

वाट्सएप ने इस साल ग्रुप चैट और कॉलिंग को ज्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए कई नए फीचर्स जोड़े हैं। इनमें लाइव ऑनलाइन स्टेटस, चैट रिएक्शन, इवेंट RSVP और वॉइस नोट ट्रांसक्रिप्शन शामिल हैं। साथ ही, एक नया ग्रुप ऑडियो Hangouts फीचर जोड़ा गया है जिससे बड़े ग्रुप में भी लाइव बातचीत की जा सकती है।

अब वाट्सएप पर आएंगे विज्ञापन

वाट्सएप ने pdates टैब में सीमित विज्ञापन दिखाने शुरू कर दिए हैं, हालांकि निजी चैट्स अब भी पूरी तरह विज्ञापन-मुक्त और एंड-टू-एंड एंक्रिप्टेड हैं। यह कदम वाट्सएप की मोनेटाइजेशन रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

सुरक्षा के लिए नया Safety Overview पेज

वाट्सएप ने एक नया सुरक्षा फीचर भी जोड़ा है जिसका नाम है Safety Overview। यह फीचर यूजर्स को किसी भी अनजान ग्रुप में शामिल होने से पहले उस ग्रुप की जानकारी देता है और संभावित स्कैम से भी सावधान करता है।

साथी एप : खरीदा मोबाइल फोन नया है पुराना? जान लें

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने एक एप के जरिए यह सुविधा दी है कि खरीद रहे मोबाइल फोन नया है पुराना, जांच सकते हैं। इसी तरह मोबाइल फोन से संबंधित कनेक्शन भी जांच सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई और सिम कार्ड एक्टिव तो नहीं है। इसी तरह संदिग्ध लेन-देन या एप अथवा लिंक की भी जानकारी दे सकते हैं।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) की संचार साथी पहल ने दूरसंचार सुरक्षा बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। लॉन्च के बाद से, इस मोबाइल ऐप छह महीनों के भीतर 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड किया जा चुका है। इसके लिए दूर संचार विभाग ने संचार साथी एप जारी किया है। भारत की व्यापक भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखते हुए, डीओटी ने अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करके ऐप की पहुँच का विस्तार किया है। धोखाधड़ी वाले कॉल और संदेशों की रिपोर्टिंग को और भी आसान बना दिया गया है, अब उपयोगकर्ता कुछ ही टैप में सीधे अपने कॉल और एसएमएस लॉग से रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।

अपनी शुरुआत से अब तक, संचार साथी पहल के तहत 5.35 लाख से ज़्यादा खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट वापस मिल चुके हैं। नागरिकों की रिपोर्ट के आधार पर 1 करोड़ से ज़्यादा अनधिकृत मोबाइल कनेक्शन काटे गए हैं, और चक्षु सुविधा के ज़रिए चिह्नित 29 लाख से ज़्यादा मोबाइल नंबरों को निष्क्रिय किया गया है। संचार साथी पोर्टल पर 16.7 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, जो इस नागरिक-केंद्रित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) भी लागू किया है, जो वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम से जुड़े मोबाइल नंबरों का आकलन और वर्गीकरण करता है। यह उपकरण बैंकों, एनबीएफसी और यूपीआई सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने में सक्षम बनाता है। परिणामस्वरूप, 34 वित्तीय संस्थानों ने एफआरआई रेटिंग के आधार पर 10.02 लाख बैंक खातों/भुगतान वॉलेट को फ्रीज कर दिया है और 3.05 लाख खातों पर डेबिट/क्रेडिट प्रतिबंध लगा दिए हैं।

16 मई 2023 को लॉन्च किए गए पोर्टल की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, दूरसंचार विभाग ने 17 जनवरी 2025 को संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो उपयोगकर्ताओं को दूरसंचार सुरक्षा सेवाओं तक सीधी और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करता है। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपनी दूरसंचार पहचान की सुरक्षा करने और संभावित धोखाधड़ी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है।

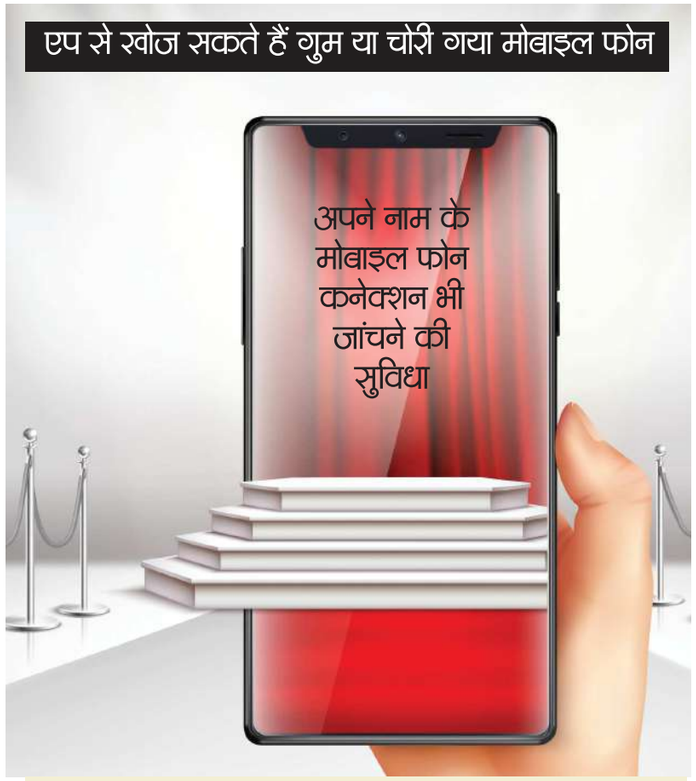

संचार साथी मोबाइल ऐप की विशेषताएं

- संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करें।
- मोबाइल फोन लॉग से सीधे संदिग्ध कॉल और एसएमएस की तुरंत रिपोर्ट करें।
- अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन जानें।
- अपने नाम से पंजीकृत सभी मोबाइल नंबरों को देखें और प्रबंधित करें, जिससे अनधिकृत कनेक्शनों का पता लगाने और उन्हें हटाने में मदद मिलेगी।
- खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करना।
- यदि आपका मोबाइल डिवाइस खो जाए या चोरी हो जाए तो उसे तुरंत ब्लॉक करें, ट्रेस करें और रिकवर करें।
- मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता जानें।
- खरीदारी करने से पहले आसानी से सत्यापित करें कि हैंडसेट असली है या नहीं।

संचार साथी मोबाइल ऐप यहां से डाउनलोड किया जा सकता है एंड्रॉइड
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dot.app.sancharsaathi
https://apps.apple.com/app/sanchar-saathi/id6739700695

अब घर बैठे जांचें चांदी के गहनों की शुद्धता! जानें जांचने का नया तरीका...

अगर आप चांदी के गहनों, में निवेश करते हैं, तो यह खबर आपके, लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर चांदी, में मिलावट की, समस्या होती है। लेकिन अब, भारतीय मानक ब्यूरो (**BIS**) ने, एक नई सुविधा, शुरू की है। अब आप अपने, मोबाइल फोन से ही, चांदी के गहनों की, शुद्धता जांच सकते हैं। यह **Silver Purity** जांचने, का एक नया, और आसान तरीका है।

ऐसे करें BIS Care App का इस्तेमाल

1. Silver Purity जांचने के लिए, आप BIS Care App का, उपयोग कर सकते हैं।
2. सबसे पहले Google Play Store या Apple App Store से BIS Care App डाउनलोड करें।
3. ऐप खोलने के बाद, 'Verify HUID' विकल्प पर क्लिक करें।
4. गहने पर मौजूद, छह अंकों का कोड, दर्ज करें।
5. कुछ ही सेकंड में, गहने की पूरी, जानकारी स्क्रीन पर, आ जाएगी।
6. इस तरह आप Silver Purity की, पुष्टि कर सकते हैं।

चांदी की शुद्धता जांचना अब हुआ आसान!

सोने की तरह अब, चांदी के गहनों पर, भी हॉलमार्किंग अनिवार्य, होने वाली है। हालांकि, फिलहाल यह स्वैच्छिक, है। बीआईएस ने चांदी के, गहनों पर कुछ, खास चिह्न अनिवार्य, किए हैं। इससे ग्राहक, आसानी से गहनों की, शुद्धता पहचान सकते हैं।

चांदी के गहनों पर ये चिह्न होंगे

1. BIS का तिकोना निशान यह शुद्धता की गारंटी है।
2. अंग्रेजी में 'SILVER' शब्द इससे पता चलेगा कि यह चांदी है।
3. शुद्धता का ग्रेड- यह बताएगा कि गहने में कितनी चांदी है।
4. छह अंकों का कोड - यह एक डिजिटल कोड है।

चांदी में मिलावट एक बड़ी समस्या

चांदी के गहनों में, मिलावट एक आम, समस्या है। कई बार ग्राहक, को पता नहीं, चलता कि गहने, में कितनी चांदी है। कई बार तो गहनों, में 50 प्रतिशत भी, चांदी नहीं होती। बीआईएस का यह, नया कदम ग्राहकों, को इस समस्या से, बचाने में मदद, करेगा।

ऐप डाउनलोड लिंक - BIS Care App Download: https://www.google.com/search?q=https://play.google.com/store/apps/details%xFid%xDcom.bis.biscare&sei=_yxAaKPWJIKcseMPhInKyQk

79 वें

स्वतंत्रता दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं!

आइए हम अपने वीर शहीदों को नमन करें
और एक मज़बूत भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।